EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims Mains Essay

Useful For Prelims

Date: 15 - Nov - 2025

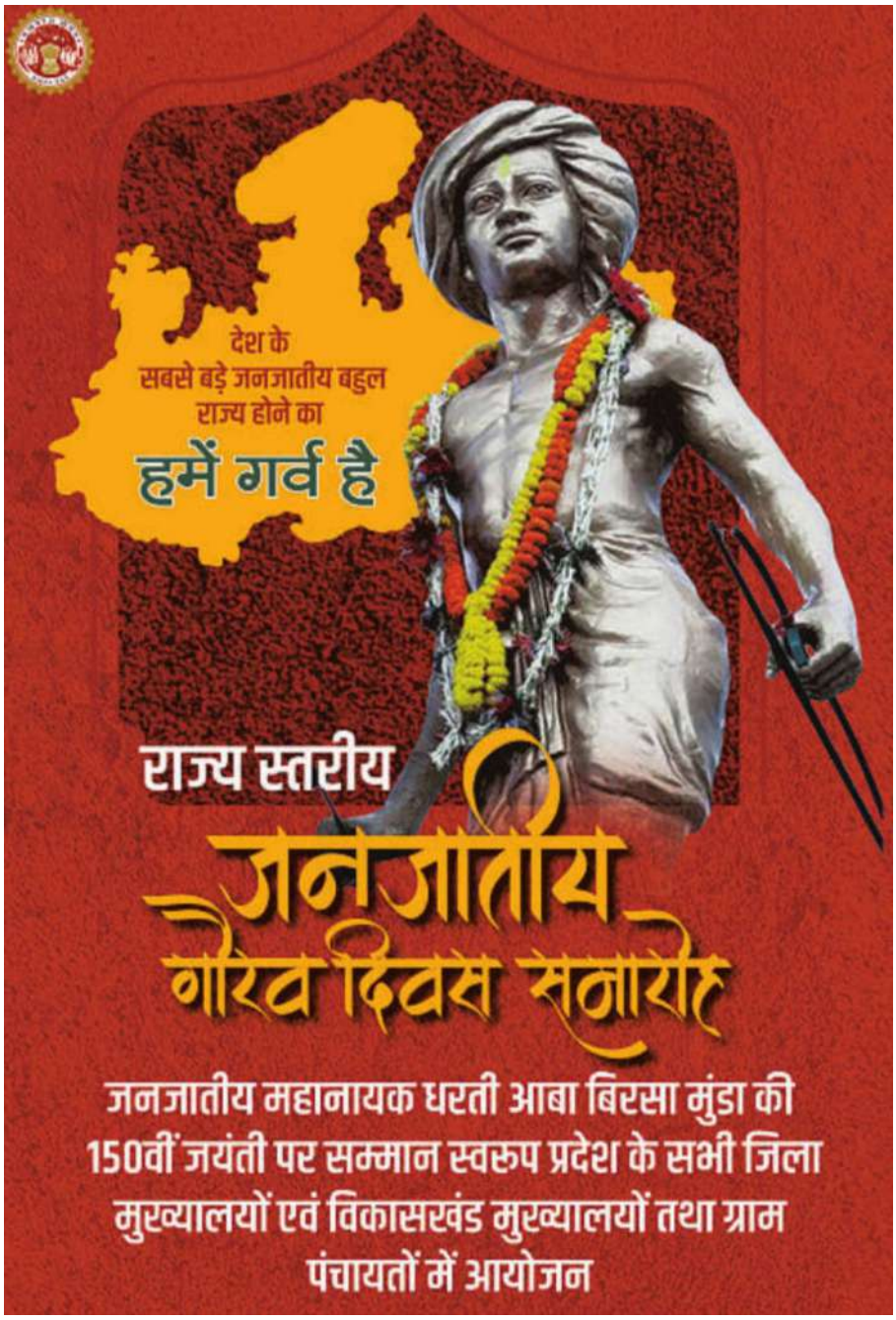

Jansatta Page No-17

सख्ती

अमेरिका की सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा

एच-1बी वीजा खत्म करने का विधेयक लाने की तैयारी

न्यूयार्क/वाशिंगटन, 14 नवंबर (भाषा)।

अमेरिका की एक सांसद ऐसा विधेयक पेश करने जा रही हैं जिसका उद्देश्य एच-1बी वीजा कार्यक्रम को 'पूरी तरह समाप्त' करना और इससे मिलने वाली नागरिकता खत्म करना है, जिससे वीजा समाप्त होने पर लोगों को 'वापस घर लौटने के लिए मजबूर' होना पड़ेगा।

जार्जिया से कांग्रेस सदस्य मार्जरी टेलर ग्रीन ने गुरुवार को 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'मेरे प्रिय अमेरिकी साथियो, मैं एक विधेयक पेश कर रही हूं जिसमें एच-1बी वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव है।

यह कार्यक्रम लंबे समय से धोखाधड़ी और दुरुपयोग से भरा रहा है और दशकों से अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनता रहा है।' उन्होंने कहा कि उनके विधेयक में सिर्फ एक छूट होगी और अमेरिकियों को जीवनरक्षक सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों और नर्स जैसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए प्रति वर्ष 10,000 वीजा की सीमा होगी। ग्रीन ने यह भी कहा कि इस 10,000 की सीमा को भी अगले 10 वर्षों में धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। अमेरिकी सांसद ने कहा कि उनका विधेयक नागरिकता का रास्ता भी बंद कर देगा, जिससे वीजा धारकों को इसकी अवधि समाप्त होने पर स्वदेश लौटना होगा। उन्होंने कहा, 'ये वीजा किसी विशेष समय पर विशेषज्ञता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू किए गए थे। लोगों को यहां आकर हमेशा के लिए रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हम उनकी विशेषज्ञता के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं लेकिन साथ ही हम चाहते हैं कि वे अपने देश लौट जाएं।'

जार्जिया से कांग्रेस सदस्य मार्जरी टेलर ग्रीन ने गुरुवार को 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'मेरे प्रिय अमेरिकी साथियो, मैं एक विधेयक पेश कर रही हूं जिसमें एच-1बी वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम लंबे समय से धोखाधड़ी और दुरुपयोग से भरा रहा है और दशकों से अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनता रहा है।' उन्होंने कहा कि उनके विधेयक में सिर्फ एक छूट होगी और अमेरिकियों को जीवनरक्षक सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों और नर्स जैसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए प्रति वर्ष 10,000 वीजा की सीमा होगी। ग्रीन ने यह भी कहा कि इस 10,000 की सीमा को भी अगले 10 वर्षों में धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। अमेरिकी सांसद ने कहा कि उनका विधेयक नागरिकता का रास्ता भी बंद कर देगा, जिससे वीजा धारकों को इसकी अवधि समाप्त होने पर स्वदेश लौटना होगा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एच-1बी वीजा के दुरुपयोग को रोकने के लिए, खासकर प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा इसके इस्तेमाल को लेकर कड़ा अभियान शुरू किया है।

भारतीय पेशेवर खासतौर से प्रौद्योगिकी कर्मचारी और चिकित्सक एच-1बी वीजा धारकों का सबसे बड़ा समूह हैं।

Jansatta Page No-10

जयशंकर ने गुतारेस से मुलाकात की, बोले

वैश्विक व्यवस्था पर उनकी समझ महत्त्वपूर्ण

संयुक्त राष्ट्र, 14 नवंबर (भाषा)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस से मुलाकात की और कहा कि वह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था एवं बहुपक्षवाद पर उसके प्रभावों को लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के आकलन को महत्त्व देते हैं।

जयशंकर ने भारत की विकास यात्रा के प्रति गुतारेस के निरंतर समर्थन के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। जयशंकर ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'न्यूयार्क में आज संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मिलकर अच्छा लगा। मौजूदा वैश्विक व्यवस्था और बहुपक्षवाद पर उसके प्रभावों को लेकर उनकी समझ महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रीय संकटों पर उनके विचारों की भी सराहना की।' यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई जिसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश, उप-स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल और भारत के स्थायी मिशन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारत के विकास और उन्नति के लिए गुतारेस के स्पष्ट और निरंतर समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि वह जल्द ही भारत यात्रा पर आएंगे। इससे पहले, जयशंकर कनाडा में हुए जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो सहित कई वैश्विक नेताओं और समकक्षों से हुई।

जयशंकर ने भारत की विकास यात्रा के प्रति गुतारेस के निरंतर समर्थन के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। जयशंकर ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'न्यूयार्क में आज संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मिलकर अच्छा लगा। मौजूदा वैश्विक व्यवस्था और बहुपक्षवाद पर उसके प्रभावों को लेकर उनकी समझ महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रीय संकटों पर उनके विचारों की भी सराहना की।' यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई जिसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश, उप-स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल और भारत के स्थायी मिशन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

Jansatta Page No-10

थोक महंगाई में अक्तूबर में 1.21 फीसद की गिरावट आई

27 महीने के निचले स्तर पर, दालों में अक्तूबर में 16.50 फीसद की गिरावट दर्ज की गई

नई दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा)।

दालों और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के साथ-साथ ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में नरमी से थोक महंगाई में अक्तूबर में गिरावट दर्ज की गई और यह 27 महीने के निचले स्तर शून्य से नीचे 1.21 फीसद रही। थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) आधारित महंगाई सितंबर में 0.13 फीसद और अक्तूबर 2024 में 2.75 फीसद रही थी।

उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा, 'अक्तूबर 2025 में महंगाई में गिरावट की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, बिजली, खनिज तेलों और मूल धातुओं के विनिर्माण आदि की कीमतों में नरमी रही।' थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर सितंबर में 5.22 फीसद के मुकाबले अक्तूबर में

8.31 घटी। प्याज, आलू, सब्जियों और दालों की कीमतों में गिरावट देखी गई।

सब्जियों की महंगाई दर में अक्तूबर में 34.97 फीसद की गिरावट आई जबकि सितंबर में यह 24.41 फीसद थी। दालों में अक्तूबर में 16.50 फीसद की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आलू और प्याज में यह क्रमशः 39.88 फीसद और 65.43 फीसद रही। विनिर्मित उत्पादों के मामले में महंगाई सितंबर के 2.33 फीसद से घटकर 1.54 फीसद हो गई। ईंधन और बिजली की कीमतें अक्तूबर में 2.55 फीसद कम हुईं जबकि पिछले महीने इनमें 2.58 फीसद की गिरावट आई थी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के कार्यकारी निदेशक पारस जसराय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बाकी समय में अनुकूल तुलनात्मक आधार से थोक महंगाई में गिरावट का दौर जारी रहने की उम्मीद है।

ऐसे में इंडिया रेटिंग्स का अनुमान है कि नवंबर 2025 में थोक महंगाई में गिरावट एक फीसद से कम रहेगी।' माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में 22 सितंबर से प्रभावी कटौती के बाद थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) आधारित महंगाई में अपेक्षा के अनुरूप गिरावट आई है।

कर दरों को युक्तिसंगत बनाने के तहत दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई जिसके तहत चार-स्तरीय कर ढांचे को घटाकर पांच और 18 फीसद की दो श्रेणी में लाया गया।

रुपया चार पैसे बढ़कर 88.66 प्रति डालर पर बंद

नई दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा)।

रुपया शुक्रवार को चार पैसे की तेजी के साथ 88.66 प्रति डालर पर बंद हुआ। अमेरिकी डालर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने घरेलू मुद्रा पर दबाव बनाया। बाजार बंद होने के समय घरेलू शेयर बाजार में तेजी और बिहार चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को मिले व्यापक जनादेश से रुपये को निचले स्तर पर समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि हालांकि, अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपये में तेज बढ़त को रोक दिया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया, डालर के मुकाबले 88.70 पर खुला।

भारत, कनाडा खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाएंगे

नई दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा)।

भारत और कनाडा ऊर्जा बदलाव और नए युग के औद्योगिक विस्तार के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाएंगे।

इस संबंध में दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देश भारत के विमानन क्षेत्र की वृद्धि का लाभ उठाते हुए निवेश और व्यापार के अवसरों की पहचान करने और उनका विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के निमंत्रण पर कनाडा के निर्यात संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक वृद्धि मंत्री मनिंदर सिद्धू 11 से 14 नवंबर के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे।

एक संयुक्त बयान में कहा गया कि मंत्रियों ने भारत-कनाडा आर्थिक साझेदारी की मजबूती और निरंतरता की पुष्टि की। साथ ही सतत संवाद, आपसी सम्मान और दूरदर्शी पहलों के जरिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

जनादेश 2025 बिहार विधानसभा चुनाव

दैनिक जागरण
पटना, 15 नवंबर, 2025
www.jagran.com

₹ 369 करोड़ है राणा कौशल प्रताप सिंह की संपत्ति, इस चुनाव में सर्वाधिक धनी प्रत्याशी रहे लौरिया में वीआइपी से, हार गए हैं

₹ 67 करोड़ है शंभूनाथ यादव पर देनदारी, इस चुनाव में सर्वाधिक देनदारी वाले प्रत्याशी रहे ब्रह्मपुर में राजद से, हुलास पांडे को हराया

क्षेत्रवार पार्टियों और गठबंधनों को सीटें

49 तिरहुत राजग : 44, महागठबंधन : 5
भाजपा : 25, जदयू : 13, लोजपा आर : 5, रालोमा : 1, राजद : 3, कांग्रेस : 2

22 शाहाबाद राजग : 19, महागठबंधन : 2, अन्य : 1
भाजपा : 8, जदयू : 7, राजद : 1, बसपा : 1, लोजपा आर : 2, रालोम : 2, भाकपा माले : 1

24 सारण राजग : 20, महागठबंधन : 4
भाजपा : 10, जदयू : 9, राजद : 4, लोजपा आर : 1

47 मगध राजग : 38, महागठबंधन : 9
भाजपा : 14, जदयू : 15, लोजपा आर : 5, राजद : 8, भाकपा माले : 1, हम : 4

27 अंग क्षेत्र राजग : 26, महागठबंधन : 1
जदयू : 14, भाजपा : 9, लोजपा आर : 2, हम : 1, राजद : 1

37 मिथिला राजग : 31, महागठबंधन : 6
जदयू : 14, भाजपा : 15, लोजपा आर : 1, राजद : 5, माकपा : 1, रालोम : 1

13 कोसी राजग : 10, महागठबंधन : 3
जदयू : 8, भाजपा : 1, लोजपा आर : 1, राजद : 2, आइआइपी : 1

24 सीमांचल राजग : 14, महागठबंधन : 5, अन्य : 5
भाजपा : 7, जदयू : 5, एआइएमआइएम : 5, कांग्रेस : 4, लोजपा आर : 2, राजद : 1

सुरक्षित सीटों में 35 पर बाजी मार ले गया एनडीए, महागठबंधन के खाते में मात्र पांच

सौरभ पांडेय • जागरण

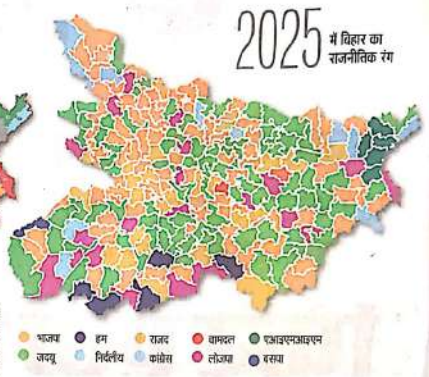

पटना : प्रायः हर चुनाव में जिस गठबंधन या दल को सुरक्षित श्रेणी की सीटों पर सर्वाधिक सफलता मिलती है, सरकार उसी की बनती है। विधानसभा के पहले चुनाव से लेकर अब तक का यही रिकार्ड रहा है। पिछले तीन चुनावों का आकलन करें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 2010 में एनडीए के प्रति लहर थी। तब सभी सुरक्षित सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। 2010 में एनडीए को आरक्षित श्रेणी की सीटों पर बढ़त मिली थी। तब भाजपा और जदयू को क्रमशः 20-20 सीटें मिली थीं। 2015 में जदयू महागठबंधन का हिस्सा रहा। तब महागठबंधन ने बंपर बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। उसे बिहार की कुल 243 में से 178 सीटों पर जीत मिली थी। तब उसकी जीत में इस श्रेणी की सीटों का अमूल्य योगदान रहा। विधानसभा में इस श्रेणी की 40 सीटें हैं। उनमें 38 अनुसूचित जाति के लिए और दो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए ने बहुमत के आधार पर पुनर्वापसी की। तब इस श्रेणी की सीटों ने उसकी जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बार भी आरक्षित श्रेणी की सर्वाधिक सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। वस्तुतः सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति-जनजाति की अपेक्षा दूसरे वर्ग के मतदाताओं का निर्णय अधिक प्रभावी हो जाता है। जातीय वर्चस्व वाले बिहार के चुनावी राजनीति में उन सीटों पर यही केमेस्ट्री काम कर जाती है।

महेश्वर हजारी   सुनील कुमार   कुमार सर्वजीत   ज्योति देवी

2025 में एनडीए में जदयू ने 15, भाजपा ने 13, लोजपा-रामविलास ने आठ, हम ने चार, जबकि महागठबंधन में राजद ने 20, कांग्रेस ने 11, माले ने छह, भाकपा, माकपा और वीआइपी ने इस श्रेणी की एक-एक सीट पर प्रत्याशी दिए थे। जदयू को 14, भाजपा को 12, लोजपा-रामविलास को पांच, हम को चार सीटों पर सफलता मिली है। राजद को चार, कांग्रेस के खाते में एक सीट आई है।

जदयू धोरैया, राजगीर, फुलवारी, मसौढ़ी, राजपुर, त्रिवेणीगंज, सिंहेश्वर, सोनबरसा, कुशेश्वरस्थान, सकरा, भोरे, राजापाकड़, कल्याणपुर, अलौली

भाजपा पातेपुर, रोसड़ा, कोढ़ा, बनमनखी, पीरपैंती, कटोरिया, मोहनिया, रामनगर, हरसिद्धि, बगहा, राजनगर, अगिआंव

लोजपा-रामविलास चेनारी, रजौली, बोचहा, दरौली, बखरी

हम कुटुंबा, इमामगंज, बाराचट्टी, सिकंदरा

राजद मखदुमपुर, बोधगया, रानीगंज, गरखा **कांग्रेस** मनिहारी

2020 में भाजपा 11, जदयू सात पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) तीन और विकासशील इंसान पार्टी ने एक सीट जीती। महागठबंधन में राजद नौ, कांग्रेस पांच सीटों पर विजयी रही थी। तब इस श्रेणी की सीटों पर भाजपा ने 16, जदयू ने 15, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने तीन, विकासशील इंसान पार्टी ने एक प्रत्याशी दिए थे। महागठबंधन में राजद द्वारा 19 और कांग्रेस द्वारा 14 प्रत्याशी उतारे गए थे।

21 मंत्री भाजपा कोटे के रहे, उनमें से हरि सहनी, जनक राम, संतोष सिंह एवं मोती लाल प्रसाद चुनाव नहीं लड़े। चुनाव जीते : सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार, रेणु देवी, मंगल पांडेय, कृष्ण कुमार मंटू, जीवेश मिश्रा, राजू कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह बबलू, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, संजय सरावगी, कृष्णनंदन पासवान, सुरेंद्र मेहता, केदार गुप्ता, विजय कुमार मंडल, डा. सुनील कुमार

14 मंत्री जदयू कोटे के रहे। उनमें से अशोक चौधरी चुनाव नहीं लड़े। सुमित कुमार चकाई में हार गए। चुनाव जीते : विजय कुमार चौधरी, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, मदन सहनी, महेश्वर हजारी, शीला कुमारी, सुनील कुमार, जयंत राज, मोहम्मद जमा खान, रत्नेश सदा, विजय मंडल

2020 के विधानसभा चुनाव में हारने वाले मंत्री
जदयू से : जय कुमार सिंह, कृष्णनंदन वर्मा, रामसेवक सिंह, शैलेश कुमार, लक्ष्मेश्वर राय, संतोष कुमार निराला, खुर्शीद उर्फ फिरोज, रमेश ऋषिदेव
भाजपा से : बृज किशोर बिंद और सुरेश कुमार शर्मा

अधिक व कम अंतर से जीत

अधिक अंतर	प्रत्याशी	कम अंतर	प्रत्याशी
73,572	कलाधर प्रसाद मंडल, जदयू : रुपौली	27	राधाचरण साह, जदयू : संदेश
59,079	संजीव चौरसिया, भाजपा : दीघा, पटना	30	सतीश कुमार सिंह यादव, बसपा : रामगढ़
58,191	राजेंद्र कुमार गुप्ता, लोजपा आर : सुगौली	95	महेश पासवान, भाजपा, अगिआंव
58,135	बुलो मंडल, जदयू : गोपालपुर	112	चेतन आनंद, जदयू : नवीनगर
57,206	रमा निषाद, भाजपा : औराई	221	मनोज विश्वास, कांग्रेस : फारबिसगंज
55,465	नरेंद्र नारायण यादव, जदयू : आलमनगर	389	संगीता देवी, लोजपा आर : बलरामपुर
55,428	कौशल किशोर, जदयू : राजगीर	602	अभिषेक रंजन, कांग्रेस : चनपटिया
55,159	लेशी सिंह, जदयू : धमदाहा	793	राहुल कुमार, राजद : जहानाबाद
54,849	नीतीश मिश्रा, भाजपा : झंझारपुर	881	कुमार सर्वजीत, राजद, बोधगया
54,498	श्रेयसी सिंह, भाजपा : जमुई	981	अरुण कुमार, लजपा आर, बख्तियारपुर

इस बार खूब ठनी थी दबंगों में हारे-जीते दोनों खेमों के लड़ाके

विनय कुमार, • जागरण

पटना : इस बार बाहुबल की अंतर्कथा से संबंधित दो अध्यायों पर ध्यान अपेक्षित है। दशकों बाद लालू प्रसाद रोड-शो के लिए निकले तो उस दानापुर में, जहां से जेल में बंद बाहुबली रीतलाल यादव पर राजद ने दांव लगा रखा था। उससे पहले सासाराम में राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी नामांकन के तत्काल बाद हो चुकी थी। राजद यह दोनों सीटें हार चुका है। दबंग माने जाने वाले उसके कई प्रत्याशी दूसरी जगहों पर भी बुरी तरह मात खाए हैं। हालांकि, ऐसे ही नाम-काम वाले एनडीए के प्रत्याशियों का बेड़ा पार लग गया है। संसदीय राजनीति में बिहार से बाहुबलियों की जीत और उद्भव का श्रेय वस्तुतः काली पांडेय को दिया जाता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। चुनावी राजनीति में बाहुबल के प्रदर्शन की एक पटकथा, बूथ कैप्चरिंग से भी जुड़ी है, जिसका श्रेय भी बिहार को ही जाता है। कांग्रेस के शासन-काल में 1957 में हुए चुनाव में बेगूसराय जिला के रचियाही गांव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुई थी। उसके आरोपित रहे कामदेव सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह पिछली बार मटिहानी से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार हार गए। हालांकि, इस बार के चुनाव में बाहुबल की अनंत कथा देश-दुनिया तक गूंजी। सबसे तगड़ी और चर्चित लड़ाई मोकामा की रही, जहां बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को

हारे

दानापुर : राजद से रीतलाल यादव
मोकामा : राजद से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी
ब्रह्मपुर : लोजपा-रामविलास से हुलास पांडेय
बाढ़ : राजद से कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया
लालगंज : मुन्ना शुक्ला की पुत्री शिवानी शुक्ला
बेलागंज : सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव, राजद से

जीते

मोकामा : जदयू से अनंत सिंह
एकमा : जदयू से धूमल सिंह
मटिहानी : राजद से बोगो सिंह
कुचायकोट : जदयू से अमरेंद्र पांडेय
रघुनाथपुर : शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहेब राजद से
मांझी : प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर जदयू से
बनियापुर : जदयू के केदारनाथ सिंह, जो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं
शाहपुर : विशेश्वर ओझा के पुत्र राकेश रंजन, भाजपा से
तरारी : सुनील पांडेय के पुत्र विशाल प्रताप भाजपा से
संदेश : जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के राधाचरण साह
वारसलीगंज : अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी, राजद से
नवादा : राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, जदयू से
बेलागंज : जदयू की मनोरमा देवी
नवीनगर : आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद, जदयू से

Dainik Jagaran Page No-2

राजग की आंधी

प्रचंड बहुमत : 83% सीटों पर जीता राजग, पटना की 14 में 11 पर जीत

विपक्ष धड़ाम : राजद-कांग्रेस समेत सबका प्रदर्शन खराब, वीआइपी साफ

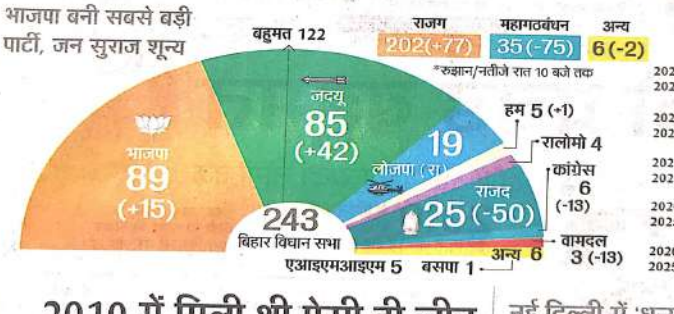

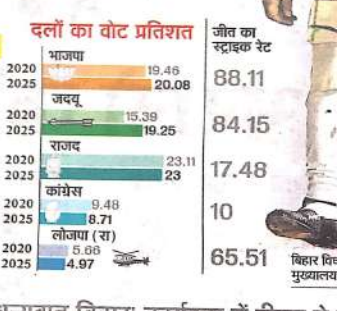

2010 में मिली थी ऐसी ही जीत

नई दिल्ली में 'धन्यवाद बिहार' कार्यक्रम में पीएम ने

Dainik Jagaran Page No-3

महिलाओं को दस हजार, वृद्धजन पेंशन में बढ़ोतरी और 125 यूनिट मुफ्त बिजली बन गया गेमचेंजर

भुवनेश्वर वात्स्यायन • जागरण

पटना : मतदान केंद्रों पर जिस हिसाब से महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें दिख रही थीं उस समय ही यह तय हो गया था कि यह कतार नीतीश कुमार के लिए ही है। यह बात उस समय और पुख्ता हो गई थी जब वोटिंग से लौट रही महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दस हजार रुपये मिलने की बात जोरदार तरीके से की। साथ चल रही महिलाओं का हाथ पकड़कर कहा कि इसे नहीं मिला है, पर चुनाव के बाद मिल ही जाएगा। कई जगहों पर महिलाओं का यह स्लोगन भी सुना गया कि जिसका खाए हैं उसका तो गाएंगे ही न। चुनाव में एनडीए की झोली जिस तरह से बढ़ी उसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बड़ी भूमिका रही।

एनडीए की जीत के जो पांच बड़े फैक्टर रहे उसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पहले नंबर पर रहा। महिलाओं के बीच नीतीश कुमार के प्रति सकारात्मक धारणा उनके लिए कैडर वोट की तरह दिखी। महिलाओं से जब बूथों पर बात हुई तो उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा अपने बच्चों के हित में किए गए काम को भी खूब गिनाया। तेजस्वी यादव ने भी चुनाव के दौरान यह कहना शुरू कर दिया था कि वह जीविका दीदी को तीस हजार रुपये देंगे। पर महिलाओं ने तय किया कि जहां से अभी मिल रहा उसी पर अपने को केंद्रित किया जाए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आने वाले समय में दो लाख रुपये मिलने की बात महिलाओं को खूब पसंद आई।

इस चुनाव का जो परिणाम आया उसमें दूसरी सबसे बड़ी भूमिका वृद्धजन पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर देने की रही। चुनाव के पहले ही वृद्धजन योजना पेंशन पर वृद्ध पुरुष व महिलाएं यह कहती दिखीं कि अपना बेटा भी सौ रुपये देने में सोचता है। वहीं नीतीश कुमार तो 1100 रुपये दे रहे। अगर पति-पत्नी हैं तो एक घर में 2200 रुपये आ जा रहे। जो दे रहा है उसका तो ध्यान रखेंगे ही। वृद्धों की बड़ी संख्या इस वजह से नीतीश कुमार के साथ दिखी और परिणाम भी दिखा। चुनाव घोषणा के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया कि सभी तरह के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह सुविधा भी तत्काल प्रभाव से चुनाव के पहले लागू हो गई। इसका सभी तरह के वोटर चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी सभी पर असर दिखा। यह वोट में कन्वर्ट हुआ।

इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित एनडीए के सभी स्टार प्रचारकों ने लालू-राबड़ी के शासनकाल दौरान बिहार में जो विधि-व्यवस्था थी उसकी खूब याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंच से उस कट्टा वाले आडियो-वीडियो की बात की जिसमें यह दिखाया गया था कि अगर तेजस्वी आते हैं तो किस तरह से गोली चलेगी। नई पीढ़ी के साथ-साथ पुरानी पीढ़ी के वोटरों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा।

नीतीश कुमार ने 84 चुनावी जनसभाएं कीं, 11 सभाएं सड़क मार्ग से : नीतीश कुमार ने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 84 जनसभाएं कीं। इस दौरान 73 जनसभाओं के लिए वह हेलीकाप्टर से पहुंचे। वहीं 11 सभाओं के लिए वह सड़क मार्ग से पहुंचे। दो जगहों पर रोड शो भी किया। अपनी चुनावी सभाओं के दौरान उन्होंने 1100 किमी की सड़क यात्रा की। आठ विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया।

Dainik Jagaran Page No-6

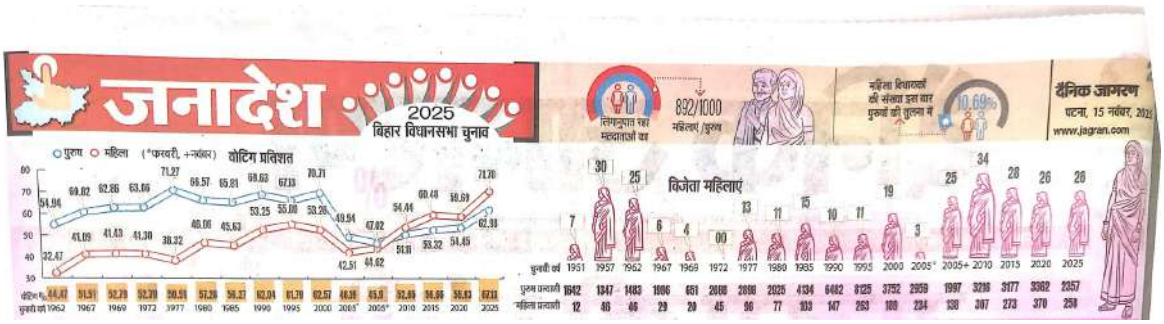

Dainik Jagaran Page No-6

वर्ष	कुल विधायक	मुसलमान विधायक
1951	330	23
1957	318	26
1962	318	22
1967	318	17
1969	318	20
1972	318	22
1977	324	24
1980	324	24
1985	324	29
1990	324	17
1995	324	21
2000	324	29
2005	243	17
2010	243	19
2015	243	24
2020	243	19
2025	243	08

हे, जबकि बिहार की जनसंख्या
ं मुसलमानों की हिस्सेदारी 17.7
तिशत है। इस बार राजद ने 18
ुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में
तारा था।

सर्वाधिक मत पाने वाले

1,40,608
मुरारी पासवान, भाजपा, पीरपैंती

1,30366
रत्नेश कुमार, भाजपा, पटना साहिब

1,27,614
विजय खेमका, भाजपा, पूर्णिया

1,26,470
श्याम रजक, जदयू, फुलवारी

1,24,826
कलाधर मंडल, जदयू, रूपौली

1,23,868
श्रेयसी सिंह, भाजपा, जमुई

1,23,698
अनिल कुमार, भाजपा, बथनाहा

1,22,480
सम्राट चौधरी, भाजपा, तारापुर

Dainik Jagaran Page No-2

..ड़ व वा अन्य सीटों की स्थिति स्पष्ट कि जिला प्रशासन ने रिजर्व फो

14 सीटों पर 48 हजार वोटरों को एक भी प्रत्याशी पसंद नहीं

नोटा का प्रभाव

प्रभात रंजन • जागरण

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने नोटा का भी प्रयोग किया। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 1278 एवं मसौढ़ी में सबसे अधिक 5146 नोटा में वोट पड़े। 2013 में शुरू हुए इवीएम पर नोटा विकल्प बना। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इवीएम पर नोटा बटन को मतदान पैनल में अंतिम विकल्प के रूप में जोड़ा। आंकड़े के अनुसार 14 विधानसभा क्षेत्र में कुल 48,558 नोटा के वोट पड़े। ऐसे में मतदाताओं को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आए।

छह विधानसभा में तीसरे नंबर पर नोटा : पटना जिले के छह विधानसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर पर नोटा रहा। इसमें दानापुर, दीघा, बांकीपुर, मोकामा, बाढ़ और मसौढ़ी शामिल हैं। वहीं चौथे नंबर पर बख्तियारपुर विधानसभा, कुम्हरार और फुलवारीशरीफ है। पालीगंज में छठे नबंर पर नोटा पर रहा।

विधानसभा क्षेत्र	नोटा में
पटना साहिब	2099
दानापुर	3242
दीघा	3102
बांकीपुर	1464
कुम्हरार	1278
मोकामा	4609
बाढ़	3631
फतुहा	3938
फुलवारीशरीफ	4844
मसौढ़ी	5146
पालीगंज	3191
मनेर	5041
बिक्रम	3338
बख्तियारपुर	3635

(नोटा पर पड़ने वाले वोट)

Dainik Jagaran Page No-5

एटीपी फाइनल्स में मुसेती को सीधे सेटों में हराया, एटीपी रैंकिंग में सिनर को पीछे छोड़ा

फिर नंबर एक बने कार्लोस अलकराज

तुरीन, एपी: स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने एक बार फिर नंबर एक की कुर्सी से जानिक सिनर को हटा दिया है। कार्लोस अलकराज ने एटीपी फाइनल्स में इटली के लारेंजो मुसेती को सीधे सेटों में हराकर साल का अंत नंबर एक रैंकिंग के साथ सुनिश्चित किया।

कार्लोस अलकराज को पुरुष टेनिस में नंबर एक रैंकिंग सुनिश्चित करने में 90 मिनट से भी कम समय लगा। अलकराज को जानिक सिनर को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 स्थान हासिल करने के लिए एटीपी फाइनल्स में एक और जीत की जरूरत थी और स्पेनिश स्टार ने यह काम पूरा करते हुए गुरुवार को इटली के लोरेंजो मुसेती को 6-4, 6-1 से हराकर अपने समूह में क्लीन स्वीप किया।

अलकराज ने कहा कि सच कहूं तो इसका मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब है। नंबर-1 होना हमेशा मेरा लक्ष्य रहता है। साल की शुरुआत में मुझे लगा कि नंबर-1 काफी दूर है, क्योंकि जानिक लगभग हर टूर्नामेंट जीत रहे थे। मध्य सीजन से अब तक मुझे लगा कि यह लक्ष्य मेरे पास है और आखिरकार मैंने इसे हासिल कर लिया।

डि मिनौर सेमीफाइनल में: अलकराज की इस जीत से आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स डि मिनौर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए, जिन्होंने इससे पहले अपना पहला एटीपी फाइनल्स मुकाबला जीता। डि मिनौर ने टेलर फ्रिट्ज को 7-6 (3), 6-3 से हराकर टूर्नामेंट में छह मैचों में अपनी पहली जीत दर्ज की।

सिनर सेमीफाइनल में

मौजूदा चैंपियन जानिक सिनर ने एटीपी फाइनल्स में अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन पर 6-3, 7-6(3) की जीत के साथ इंडोर हार्डकोर्ट पर अपनी जीत की लय को 29 मैचों तक बढ़ा दिया। सेमीफाइनल में सिनर का सामना डि मिनौर से होगा।

नंबर एक खिलाड़ी की ट्राफी के साथ अलकराज ● एएफपी

Dainik Jagaran Page No-16

डब्ल्यूटीओ में सुधार का नेतृत्व करे भारत : न्गोजी

विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक ने कहा, अच्छी गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था

- भारत के पास वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता और विश्वसनीयता
- वैश्विक व्यापार प्रणाली की मजबूती के लिए सभी से साथ काम करने की अपील

विशाखापतनम, प्रेट्र: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला ने शुक्रवार को कहा कि भारत को वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच इस संगठन में सुधार प्रक्रिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से बढ़ रही है और यह तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले देशों में से एक है।

उद्योग संगठन सीआइआइ के साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 में न्गोजी ने कहा कि डब्ल्यूटीओ को उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें सुधारने के उपायों पर चर्चा करनी चाहिए। यहां भारत नेतृत्व करने वाला बन सकता है। भारत को डब्ल्यूटीओ में सुधार प्रक्रिया में एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करने में नेतृत्व करना चाहिए कि हम एक ऐसे सिस्टम में नहीं रहें जो नियमों के बजाय शक्ति आधारित हो।

सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक ने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके पास न केवल इस क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता और विश्वसनीयता है। अमेरिका की ओर से लगाए गए उच्च टैरिफ पर न्गोजी ने कहा कि सदस्य देशों को उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने भी सार्वजनिक भंडारण जैसे मुद्दों पर चिंता जताई है और यह दोहराना कि अतीत में क्या हुआ, एक मजबूत वैश्विक व्यापार प्रणाली बनाने में मदद नहीं करेगा। उन्होंने डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों से वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए साथ काम करने की अपील की।

विशाखापतनम में शुक्रवार को आयोजित सीआइआइ के सम्मेलन को संबोधित करतीं डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला ● @सीआइआइ

अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के कार्यों पर जताई है चिंता

अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के कार्यों के तरीके पर चिंता जताई है और विवाद निवारण तंत्र में सुधार की मांग की है। डब्ल्यूटीओ एक 166-सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो व्यापार से संबंधित मुद्दों से निपटता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत 1995 से इसका सदस्य है। डब्ल्यूटीओ ने यह भी कहा कि किसी देश को अपनी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए एक बहुपक्षीय प्रणाली की भी आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देशों ने भी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर चिंताएं उठाई हैं।

72% वैश्विक व्यापार नियमों के तहत

न्गोजी ने कहा कि 72 प्रतिशत वैश्विक व्यापार अभी भी डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत हो रहा है, जो स्थिरता और पूर्वानुमानिता को साबित करता है। इस समय वैश्विक व्यापार में बड़े व्यवधान देखे जा रहे हैं। ऐसे में डब्ल्यूटीओ महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूटीओ प्रमुख ने कहा कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताएं अवसर भी प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि देशों को अमेरिका या चीन पर अपनी अधिक निर्भरता में विविधता लानी चाहिए। भारत इस समय वैश्विक सप्लाई चेन के विविधीकरण में एक बड़ा लाभार्थी है।

मुक्त व्यापार समझौतों से हमें कोई समस्या नहीं

डब्ल्यूटीओ प्रमुख ने कहा कि हमें मुक्त व्यापार समझौतों से कोई समस्या नहीं है। चाहे वह दो सदस्यों या दो समूहों के बीच हो, नियम पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ आधारित हैं। हम उन्हें खतरे के रूप में नहीं देखते और वास्तव में हम उनके साथ ठीक हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सदस्यों को अपने व्यापार में विविधता लाने की आवश्यकता है।

Dainik Jagaran Page No-17

बांग्लादेश में सलाफी समूह कर रहे फिर तख्तापलट की तैयारी

कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को आइएसआइ से मिल रहा पूरा समर्थन

- मोहम्मद यूनुस नीत अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के आगे पड़ रही कमजोर
- यूनुस स्थितियों को भांप नहीं पाए, प्रशासन ने जमात को छूट देकर बर्बादी का द्वार खोला

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: बांग्लादेश में एक खतरनाक ट्रेंड देखा जा रहा है, जहां ज्यादा से ज्यादा कट्टरवादी इस्लामी संगठन एकजुट होकर देश में इस्लामी तख्तापलट की तैयारी में हैं। 'हिफाजत ए इस्लाम' जैसे तमाम सलाफी संगठन आपस में हाथ मिला रहे हैं ताकि देश में कट्टरपंथी इस्लामी कानून थोपा जा सके। आइएसआइ कट्टरपंथियों के जरिये देश को पूरी तरह कब्जे में लेने की योजना पर अमल कर रही है।

आइएसआइ ने तेजी से बांग्लादेश और पाकिस्तान में मौजूद सलाफी संगठनों के बीच जुड़ाव बढ़ाया। ये देश में इस्लामी तख्तापलट का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके पीछे मकसद बांग्लादेश में ईरान की तर्ज पर शासन प्रणाली विकसित करना है। तब बांग्लादेश का नेतृत्व एक सुप्रीम लीडर करेगा। आइएसआइ की निगरानी में आठ हजार से ज्यादा युवाओं को देश में तमाम जगहों पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी (आइआरए) का हिस्सा बनाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन्हें आगे चलकर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स (आइआरजीसी) की तरह तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यूनुस प्रशासन द्वारा जमात पर लागू प्रतिबंध को हटाया जाना घातक साबित हो रहा है। यूनुस स्थितियों को भांप नहीं पाए और जमात को जरूरत से ज्यादा छूट दे दी। जमात पूरी तरह आइएसआइ नियंत्रित इकाई है। बांग्लादेश पर करीबी नजर रखनेवालों का कहना है कि देश में इस्लामी प्रति-क्रांति हो रही है। अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान की दखलंदाजी रोकी नहीं गई, तो भारत के लिए सिरदर्द बहुत जल्द बढ़ सकता है। सलाफी एक मुस्लिम आंदोलन है जिसका उद्देश्य इस्लाम की शुरुआती तीन पीढ़ियों (जिन्हें 'सलाफ़' कहा जाता है) के तरीकों को अपनाना है। वे कुरान और पैगंबर की सुन्नत के शाब्दिक अर्थों का पालन करने पर जोर देते हैं और धार्मिक नवाचारों को अस्वीकार करते हैं। यह आंदोलन विभिन्न समूहों में बंटा हुआ है, जिसमें राजनीति से दूर रहनेवाले शुद्धतावादी, राजनीतिक कार्यकर्ता और सशस्त्र संघर्ष के समर्थक जिहादी शामिल हैं।

मोहम्मद यूनुस (फाइल) रायटर

Dainik Jagaran Page No-18

बीबीसी ने अब डोनाल्ड ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी

लंदन, रायटर : बीबीसी (ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित वृत्तचित्र में संपादन में गलती के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी है। जबकि ट्रंप के नजदीकी लोगों ने आर्थिक क्षतिपूर्ति के साथ माफी मांगने के लिए कहा है। ट्रंप की ओर से इस संबंध में बीबीसी को नोटिस दिया गया है।

बीबीसी ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के पीछे कोई कानूनी कारण नहीं हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को साफ नीयत से इस बाबत पत्र भेजा गया है। चंद रोज पहले जब ट्रंप से संबंधित डाक्यूमेंट्री का मामला मीडिया में आया था तब ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उसके बाद बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया था। इस प्रकरण में बीबीसी के महानिदेशक और समाचार प्रमुख ने इस्तीफा भी दिया था।

Dainik Jagaran Page No-18

27 महीने के निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई

- अक्टूबर 2025 में -1.21 प्रतिशत रही थोक महंगाई
- दालों-सब्जियों की कीमतों में कमी का मिला लाभ

नई दिल्ली, प्रेट्र: इस वर्ष अक्टूबर में थोक महंगाई -1.21 प्रतिशत रही है, जो इसका 27 महीने का निचला स्तर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दालों व सब्जियों जैसी खाद्य वस्तुओं में तेज गिरावट और ईंधन व मैन्यूफैक्चरिंग वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण पिछले महीने थोक महंगाई घटी है। थोक महंगाई इस वर्ष सितंबर में 0.13 प्रतिशत और अक्टूबर 2024 में 2.75 प्रतिशत थी।

उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अक्टूबर 2025 में महंगाई की नकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, खनिज तेल और बुनियादी धातुओं की निर्माण लागत में कमी के कारण रही है। आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई में 8.31 प्रतिशत की गिरावट रही है जबकि सितंबर 2025 में यह 5.22 प्रतिशत थी। इस दौरान प्याज, आलू, सब्जियों और दालों की कीमतों में गिरावट देखी गई। अक्टूबर में सब्जियों की महंगाई दर में 34.97 प्रतिशत की गिरावट रही है। सितंबर 2025 में यह 24.41 प्रतिशत थी। इसी तरह, दालों में अक्टूबर में 16.50 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि आलू और प्याज में यह क्रमशः 39.88 प्रतिशत और 65.43 प्रतिशत थी।

मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों की महंगाई दर सितंबर की 2.33 प्रतिशत से घटकर 1.54 प्रतिशत रही है। ईंधन और बिजली की महंगाई दर -2.55 प्रतिशत रही है, जो सितंबर 2025 में 2.58 प्रतिशत थी। ईंधन और बिजली की महंगाई दर में लगातार सातवें महीने गिरावट दर्ज की गई है।

अपेक्षा के अनुरूप से थोक महंगाई में गिरावट : जानकारों का कहना है कि थोक महंगाई में यह गिरावट अपेक्षा के अनुसार है। इसका कारण यह है कि 22 सितंबर से जीएसटी की घटी दरें लागू हो गई थीं। इससे दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई थी। इसके अलावा अब जीएसटी में केवल दो दरें पांच और 18 प्रतिशत रह गई हैं। कर कटौती के बाद वस्तुओं की कीमतों में कमी से थोक और खुदरा दोनों महंगाई दर को कम किया है। पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई दर 0.25 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर पर रही है।

रेपो रेट में कटौती कर सकता है आरबीआइ

आरबीआइ खुदरा महंगाई के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति तय करता है। लेकिन खुदरा और थोक महंगाई की यह गिरावट रेपो रेट में कटौती का दबाव डालेगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर पारस जसराई का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई अब लगभग 2.5 प्रतिशत तक गिरने की उम्मीद है। हालांकि, अर्थव्यवस्था को सुस्त और कमजोर आर्थिक वृद्धि में जाने से रोकने के लिए आरबीआइ 3-5 दिसंबर को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 25-50 आधार अंक की कटौती कर सकता है।

Dainik Jagaran Page No-17

चुनाव यज्ञ निर्विघ्न संपन्न

यह संतोष का विषय है कि राज्य में नई विधानसभा और सरकार के गठन का रास्ता निर्विघ्न ढंग से साफ हो गया है। शुक्रवार को मतों की गिनती का काम पूरा हुआ और परिणाम भी आ गए। राज्य में पहले जब कभी चुनाव हुए, गड़बड़ी की आशंका बनी रहती थी। विभिन्न दलों के समर्थक आपस में लड़ते-भिड़ते रहते थे। लेकिन, इसबार के चुनाव में मामूली झड़प को छोड़ दें तो हिंसा की कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई। झड़पें तो मतगणना केंद्र पर भी होती थीं। संयोग से मतगणना भी निर्विघ्न संपन्न हो गया। लोकतंत्र की यही सुंदरता है कि लोग अलग-अलग दलों के पक्ष में मतदान करते हैं और उसके बाद जो सरकार बनती है, वह सबकी होती है। सरकार इस आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करती है कि उसके दल को संबंधित व्यक्ति ने वोट नहीं दिया। सदन के भीतर सभी दलों के सदस्य आपसी विमर्श के आधार पर आम लोगों के कल्याण की योजना बनाते हैं। जन समस्याओं को रखते हैं और निदान का उपाय करते हैं। आपस में दलीय आधार पर वैमनस्यता का भाव रखने वाले कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि उनके नेता किस तरह अपने समकक्ष के साथ मित्रता का भाव रखते हैं। चुनाव के समय एनडीए के घटक दलों ने साझे में जो घोषणा पत्र जारी किया है। उम्मीद की जा सकती है कि नई सरकार प्राथमिकता से उन योजनाओं का लागू करे।

एनडीए के घटक दलों ने साझे में घोषणा पत्र जारी किया है। इससे जनता को काफी उम्मीदें हैं।

Dainik Jagaran Page No-14

महिलाओं के लिए घोषित योजनाओं ने निभाई भूमिका **लोकलुभावन** एक करोड़ से अधिक आधी आबादी लाभान्वित हुई

नीतीश की दसहजारी गारंटी ने तय कर दी जीत

राकेश शर्मा
नई दिल्ली, 14 नवंबर।

चुनाव से पहले एक करोड़ से अधिक महिलाओं को महिला रोजगार योजना के तहत खाते में मिली दस हजार की राशि, शराब बंदी, नौकरी व पंचायत में आरक्षण के साथ दूसरी योजनाओं ने बढ़ाया महिलाओं का विश्वास।

इस चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मत फीसद 9 फीसद से अधिक रहा, इससे पहले महिलाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड में दे चुकी हैं मौजूदा सरकार का साथ।

बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार की दस हजारी गारंटी ने राजग को प्रचंड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं को उनके खाते में दस हजार रुपए की राशि दी गई।

यह घोषणा प्रदेश में बाकी सभी मुद्दों पर भारी पड़ गई और विपक्ष इसकी काट नहीं कर सका। इस राशि को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने जुबानी हमला तक बोला। दावा किया कि सरकार बनने के बाद यह राशि सरकार को लौटानी पड़ेगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर चुनावी सभा में दावा किया कि विपक्ष झूठा भ्रम फैला रहा है। यह राशि लौटाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री के बयान पर विश्वास कर राजग को पूरा समर्थन दिया, जिसके बल पर राजग साल 2010 के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही।

इस मुद्दे की बदौलत राजग कैमूर, अरवल, रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद जिले में भी खाता खोलने में कामयाब रही, जबकि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इन जिलों में महागठबंधन के विधायक थे।इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कर्मियों और जीविका दीदियों (स्व-सहायता समूहों की महिलाएं) का मानदेय बढ़ाकर, मुफ्त बिजली (प्रत्येक घर को 125 यूनिट) और पेंशन राशि बढ़ाकर आर्थिक सहायता दी। साथ ही पहले से चल रही शराबबंदी, पुलिस भर्ती में 35 फीसद आरक्षण और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण का लाभ भी राजग को मिला। इन सभी योजनाओं का असर चुनाव में दिखा। दो चरण में हुए मतदान के दौरान 71.78 फीसद महिलाएं मतदान केंद्र पहुंची थी, जबकि पुरुषों की भागीदारी केवल 62.98 फीसद रही।

दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रध्यापक संतोष झा का कहना है कि महिलाओं का 8.8 फीसद बढ़ा हुआ मतदान और उनकी ओर केंद्रित कल्याण योजनाओं ने चुनावी समीकरण ही बदल दिए। एक रपट के मुताबिक बिहार में करीब 3.5 करोड़ मतदाता महिलाएं हैं और उनकी मतदान सहभागिता कई चुनावों से लगातार बढ़ रही है। राजग ने महिलाओं को सिर्फ जाति-आधारित वोट बैंक के रूप में नहीं देखा, बल्कि महिला पहचान को एक नए और मजबूत वोट बैंक के रूप में उभारा है।

बिहार से पहले ऐसा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड में भी देखने को मिल चुका है। बीते चुनाव से पहले महाराष्ट्र में 'माझी मुलगी बहन

बाकी पेज 8 पर

देश में पहली बार डिजिटल गोपनीयता कानून लागू

नई दिल्ली (वार्ता)।

व्यक्तियों की डिजिटलीकृत सूचनाओं के संरक्षण और उपयोग को विनियमित करने वाले डिजिटल व्यक्तिगत-डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम 2023 को सरकार ने इसके पारित होने के दो साल बाद आज अधिसूचित करते हुए इसे लागू कर दिया। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए संबंधित नियमावली भी जारी कर दी है तथा चार सदस्यीय डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बोर्ड (डीपीबी) का भी गठन कर दिया गया है। लम्बी बहस के बाद देश में पहली बार डिजिटल गोपनीयता कानून लागू हो रहा है।

इस अधिनियम में व्यक्ति को अपने निजी डिजिटलीकृत डेटा की सुरक्षा का अधिकार देने के साथ साथ ऐसे डाटा का वैध उद्देश्यों के लिए प्रसंस्करण किये जाने को भी कानूनी मान्यता दी गयी है। नए नियमों के तहत कंपनियों और अन्य हितधारकों को अधिनियम के तहत प्रशासनिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए 18 महीने तक का समय दिया गया। कंसेट मैनेजरों (सहमति प्रबंधकों) को पंजीकरण कराने के लिए 12 माह का समय दिया गया है। सहमति प्रबंधक डिजिटल प्लेटफार्मों के

- इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना मंत्रालय ने नियमावली की जारी
- चार सदस्यीय डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बोर्ड का भी गठन

उपयोगकर्ताओं की ओर से कार्य करते है।

इन नियमों के लागू होने के साथ, सोशल मीडिया और इंटरनेट मध्यस्थों, और उपयोगकर्ता डेटा का कारोबार करने वाली किसी भी अन्य कंपनी को डेटा प्रिंसिपल अर्थात उपयोगकर्ता का डाटा प्रसंस्करण हेतु देने के लिए उसका पूरा विवरण देते हुए उसके लिए सहमति लेनी होगी।

इन नियमों में डिजिटल मध्यस्थों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऐसे माध्यमों के लिए अलग-अलग समय-सीमाएँ भी निर्धारित की हैं जिनके अनुसार इन प्लेटफ़ॉर्म को उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा को हटाना होगा। यदि किसी वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अनुपालन के लिए ऐसे डाटा को अधिक समय तक रखना जरूरी है तो उन्हें उसके अनुसार उसको अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

कंपनियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए अपनी सहमति आसानी से वापस लेने का मौका दें। उपयोगकर्ता को ऐसे डिजिटल प्लेटफार्मों के खिलाफ डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर डिजिटल डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज करने की भी छूट होगी। सहमति प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल डेटा संरक्षण बोर्ड के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। उन्हें काम के दौरान समय-समय पर बोर्ड की शर्तों और निर्देशों को पूरा करना होगा। नियम कानून का उल्लंघन करने पर ऐसे प्रबंधकों का पंजीकरण निलंबित भी किया जा सकता है। बोर्ड पूरी तरह डिजिटल रूप से संचालित होगा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

National Sahara Page No-11

Hindustan Page No-3

भारत को डब्ल्यूटीओ में सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए

विशाखापत्तनम (भाषा)।

विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख नगोजी ओकोंजो-इवेला ने शुक्रवार को कहा कि भारत को डब्ल्यूटीओ में सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से बढ रही है और यह प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। डब्ल्यूटीओ की प्रमुख ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें सुधारने के तरीकों पर चर्चा करने की जरूरत है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक ने यहां सीआईआई के साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 में कहा, "...इसमें भारत अग्रणी हो सकता है। भारत को डब्ल्यूटीओ में सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए...। भारत को यह सुनिश्चित करने में अग्रणी होना चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था में न रहें जो नियम आधारित होने के बजाय शक्ति आधारित हो जाए।"

उन्होंने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसके पास न केवल इस क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यापकता एवं विश्वसनीयता है। अमेरिका के उच्च शुल्क का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्य देशों को अमेरिका द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत ने भी खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से अनाज भंडारण और वितरण जैसे मुद्दों पर चिंता जताई है। पिछली शिकायतों को दोहराने से एक मजबूत वैश्विक व्यापार प्रणाली बनाने में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों से वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन की इकाइयों के कामकाज के तरीके पर चिंता जताई है और विवाद निवारण तंत्र सहित डबल्यूटीओ में सुधारों की मांग की है।

डबल्यूटीओ 166 सदस्यों वाला जिनेवा स्थित एक बहुपक्षीय निकाय है जो व्यापार संबंधी मुद्दों से निपटता है। भारत 1995 से इसका सदस्य है।

नगोजी ने साथ ही कहा कि किसी देश को अपनी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की आवश्यकता हो सकती है लेकिन "आपको आगे बढ़ने के लिए एक बहुपक्षीय प्रणाली की भी जरूरत है।" उन्होंने कहा, " यही कारण है कि डब्ल्यूटीओ महत्वपूर्ण है।'

पन्ना का हीरा अब होगा और खास, मिला जीआई टैग

पन्ना (वार्ता)।

बेशकीमती रत्न हीरा की खदानों के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की धरती से निकलने वाले हीरों को जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरों की कीमत व महत्व और बढ़ जायेगा। पन्ना के हीरा अधिकारी रवि पटेल ने आज बताया कि जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैल्यू बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जीआई (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) यानी भौगोलिक संकेत एक प्रतीक है, जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जिस वस्तु को यह टैग मिलता है, वह उसकी विशेषता बताता है।

पन्ना के हीरों को जीआई टैग मिले, इसके लिए यूमन वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ ने चेन्नई स्थित संस्था में जून 2023 में आवेदन किया था। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था पूरी जांच पड़ताल और छानबीन के बाद

- **जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी वैल्यू**
- **पन्ना के हीरों का हल्का हरा रंग और कार्बन लाइन इन्हें अन्य हीरों से अलग और बेजोड़ बनाती है**

जीआई टैग देती है। जीआई टैग मिलने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस प्रोडक्ट की कीमत व महत्व बढ़ जाता है।

हीरा अधिकारी श्री पटेल ने बताया कि जिला प्रशासन, हीरा खनन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग और पद्मश्री डॉ. रजनी कांत, मानव कल्याण संघ के जीआई तकनीकी सहायता से पन्ना के हीरों को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि (जीआई टैग) प्राप्त हुई है।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की पहचान सदियों से यहां की धरती से निकलने वाले बेशकीमती हीरों के कारण है। यही वजह है कि पन्ना को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है।

जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिसका लाभ निश्चित ही पन्ना के हीरा व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा। पन्ना के हीरे न केवल कानूनी मान्यता प्राप्त करेंगे, बल्कि अब इन हीरों की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तथा उपभोक्ताओं को प्रमाणित और विश्वसनीय हीरे मिल सकेंगे। पन्ना के हीरों की अपनी एक विशेष पहचान रही है, उनका हल्का हरा रंग और कार्बन लाइन इन्हें अन्य हीरों से अलग तथा कटिंग और चमक में बेजोड़ बनाती है।

Rashtriya Sahara Page No-11

भारत में हर 50 दिन में एक नया हवाई अड्डा खोला जाता है

विशाखापत्तनम (भाषा)। नागर विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को कहा कि भारत में हर 50 दिन में एक नया हवाई अड्डा खोला जाता है, जो दुनिया में कहीं भी अभूतपूर्व है। दो दिवसीय सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन-2025 के 30वें संस्करण को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में वर्तमान में सात हवाई अड्डे हैं और राज्य में इतनी ही संख्या में हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। नायडू ने कहा, "प्रत्येक 50 दिन में हम एक नया हवाई अड्डा खोल रहे हैं, जो विश्व में कहीं भी अभूतपूर्व है और हवाई अड्डों के निर्माण, यात्री क्षमता तथा विमानन के कई अन्य क्षेत्रों में हमने इसी प्रकार की सफलता हासिल की है।" उन्होंने कहा कि राज्य में चार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं तथा विशाखापत्तनम में एक एमआरओ पारिस्थितिकी तंत्र और एक विमानन कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि राज्य में 'ड्रोन सिटी' बनाकर ड्रोन क्षेत्र का विस्तार किए जाने की उम्मीद है तथा एयरोस्पेस और विमान विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

National Sahara Page No-11

Useful For Mains

महागठबंधन के लिए महासंकट की घड़ी

महागठबंधन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता की दौड़ में राजग से एक प्रतिशत से भी कम वोटों और 15 सीटों से पिछड़ गया था तो हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा गया था। तब 70 सीटों पर लड़ी कांग्रेस 19 ही जीत पाई थी। वाम दलों का प्रदर्शन भी उससे बेहतर रहा। कांग्रेस इस बार और भी कमजोर कड़ी साबित हुई। राजद और कांग्रेस में अंत तक औपचारिक सीट बंटवारा नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप दस से भी ज्यादा सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हुआ, पर महागठबंधन और राजग के बीच मत प्रतिशत एवं सीटों में भारी अंतर बताता है कि अतीत से सबक सीखने के बजाय और अधिक गलतियां की गईं।

गठबंधन राजनीति में दलगत हितों के बीच ही संतुलन और समन्वय की राह निकालनी पड़ती है। चूंकि शह-मात की तमाम अटकलों के बीच भी राजग यह काम कर पाया, इसलिए 'सत्ता विरोधी' भाव के बजाय 'सत्ता समर्थक' चुनावी लहर दिखी। पिछले चुनाव में पिछड़ने के बाद महागठबंधन को जमीनी राजनीति में जो काम करना चाहिए था, उसके बजाय वह आपसी खींचतान में ही लगा रहा। इसे बेहतर सामाजिक समीकरण से ही पाटा जा सकता था, लेकिन इस दिशा में कुछ खास नहीं किया जा सका। मात्र 15 सीटें पाने वाले मुकेश सहनी को जिस तरह उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया, उससे महागठबंधन को चुनावी नुकसान ही हुआ। 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस के नेता और समर्थक तो बिदके ही, कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाले मुसलमान और दलित भी निराश हुए। 143 सीटों पर लड़े राजद ने जिस तरह 52 यानी लगभग 36 प्रतिशत यादव उम्मीदवार उतारे, उससे अन्य ओबीसी जातियों, खासकर ईबीसी में नकारात्मक संदेश गया। यादव-मुस्लिम जनाधारवाला राजद अन्य वर्गों को ज्यादा टिकट देकर अपना और महागठबंधन का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर सकता था।

अपने गठबंधन और सीट बंटवारे से राजग सर्वसमाज के प्रतिनिधित्व का संदेश देने में सफल रहा, लेकिन महागठबंधन ऐसा नहीं कर पाया। तेजस्वी जंगलराज के बोझ से मुक्त नहीं हो पाए

राज कुमार सिंह

महागठबंधन को मिली करारी हार उसके मनोबल पर आघात के साथ उसके भविष्य पर भी सवालिया निशान लगाने वाली है

जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रही जोड़ी ● फाइल

और उसकी पुनरावृत्ति का डर दिखा कर राजग एक बार फिर बाजी मार ले गया। राजग के मंच से लालू परिवार को महाभ्रष्ट परिवार भी कहा गया, क्योंकि लगभग पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार के मामलों में कानूनी शिकंजे में है। बेशक चुनाव में कई मुद्दे काम करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे जनता सीधे प्रभावित होती है। इसलिए इन मुद्दों पर मतदाता आम तौर पर समझौता नहीं करते।

उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार के दौरान दी गई नौकरियों का श्रेय लेते हुए मान लिया कि वे युवाओं की पसंद बन जाएंगे, पर स्वाभाविक ही मुख्यमंत्री को उस श्रेय से वंचित नहीं कर पाए। कांग्रेस कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल के आजमाए हुए 'गारंटी कार्ड' पर जोर देना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी 'राग-नौकरी' आलापते रहे। राज्य-दर-राज्य रेवड़ियां चुनावी राजनीति में निर्णायक साबित हो रही हैं। नीतीश ने भी चुनाव से पहले सवा करोड़ से भी अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर करने समेत कई लोकलुभावन घोषणाएं कीं। लोकलुभावन वादे तो तेजस्वी ने भी किए, पर बाजी बेहतर ट्रैक रिकार्ड वाले नीतीश के हाथ रही। फिर तेजस्वी आखिर तक नहीं बता पाए कि अपने वादे पूरे करने के लिए उनका ब्लूप्रिंट क्या है। राजग की तर्ज पर तेजस्वी ने महागठबंधन का विस्तार तो किया, लेकिन एकजुट तस्वीर पेश करने में विफल रहे। उन्होंने महागठबंधन के घोषणापत्र को 'तेजस्वी प्रण' का नाम देकर खुद को प्रोजेक्ट करने की कवायद ज्यादा की। वे महागठबंधन का स्वाभाविक मुख्यमंत्री चेहरा थे, लेकिन इस पर कांग्रेस की सहमति में विलंब का नकारात्मक असर पड़ा। दरअसल महागठबंधन के दो बड़े दल- राजद और कांग्रेस चुनाव प्रचार में एक साथ दिखने के बजाय परस्पर प्रतिस्पर्धा करते ज्यादा नजर आए। राहुल गांधी ने जनाधार बढ़ाने के लिए ईबीसी पर फोकस करते हुए दस सूत्रीय एजेंडा घोषित किया था, पर तेजस्वी के घोषणा पत्र में उसे ज्यादा महत्व नहीं मिला। सीट बंटवारे से लेकर घोषणापत्र और चुनावी मुद्दों तक महागठबंधन इस बार दिग्भ्रमित दिखा। बिहार अचानक गरीब राज्य नहीं बना। पलायन भी नीतीश राज में शुरू नहीं हुआ। आज भी जंगलराज चुनावी मुद्दा बनने से साफ है कि पिछले 20 साल में हालात बेहतर हुए हैं। इसके बावजूद ये गंभीर चुनावी मुद्दे बन सकते थे, लेकिन महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने भी इनके बजाय 'वोट चोरी' को मुद्दा बनाया। वोट अधिकार यात्रा निकालने के बाद लगभग दो महीने तक बिहार में उनकी अनुपस्थिति ने भी सवाल खड़े किए। विधानसभा चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि जनता की अदालत ने वोट चोरी के आरोप को खारिज कर दिया। 20 साल के नीतीश राज के बाद भी महागठबंधन को मिली करारी हार उसके मनोबल पर आघात के साथ उसके भविष्य पर भी सवालिया निशान लगाने वाली है।

पिछली बार सबसे बड़ा दल बनकर उभरा राजद इस बार आधे से भी कम रह गया तो मुख्यतः दलित जनाधार वाली लोजपा (आर) कांग्रेस से भी बड़ा दल बन गई। स्पष्ट है कि महागठबंधन के लिए यह महासंकट की घड़ी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-14

Jansatta Page No-08

Jansatta Page No-08

हर मोर्चे पर महा साबित हुआ राजग

राहुल वर्मा

राजग की इतनी बड़ी जीत का यही सार है कि जहां उसके सभी दांव कारगर रहे, वहीं महागठबंधन के सारे जतन नाकाम रहे

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाले रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग को मिले प्रचंड बहुमत ने उन दावों की हवा निकालने का काम किया, जो यह जता रहे थे कि चुनाव में बड़े कांटे की टक्कर है। राजग ने इस चुनाव को एकतरफा बना दिया और राजद, कांग्रेस और वीआइपी जैसे दलों के महागठबंधन को ऐसी करारी शिकस्त दी, जिससे उबरने में उन्हें काफी समय लग सकता है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के लिए भी यह जनादेश ऐसी सीख देने वाला साबित हुआ कि चुनाव जितवाने और जीतने में जमीन-आसमान का अंतर होता है। बिहार का जनादेश राज्य की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को भी एक बड़ी हद तक प्रभावित करेगा। भाजपा सीटों के लिहाज से राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं, जदयू ने भी पिछले चुनाव की तुलना में जबरदस्त वापसी की है। नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में पांचवें चुनाव में जीत दिलाकर उन चुनिंदा क्षत्रपों में शामिल हो गए, जो अलग-अलग राज्यों में यह करिश्मा दिखाने में सफल रहे हैं। राजग की इतनी बड़ी जीत में किसी एक पहलू की ही भूमिका नहीं हो सकती। इसका एक ही पंक्ति में यही सार निकाला जा सकता है कि जहां राजग के सभी दांव कारगर रहे, वहीं विपक्षी महागठबंधन के सभी दांव विफल साबित हुए।

राजग की जीत के कारण देखें तो बिहार चुनाव की रेस में यह गठबंधन एक तरह से 'पोल पोजीशन' यानी बढ़त की स्थिति के साथ शुरुआत करता है। गठबंधन में शामिल दलों के विविधता से भरे सामाजिक समीकरण राजग को यह स्वाभाविक बढ़त दिलाते हैं। महागठबंधन का नेतृत्व करने वाला राजद जहां अर्से से अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव गठजोड़ पर निर्भर रहा है, वहीं राजग ने अपना आधार बरकरार रखते हुए नए वर्गों में भी अपनी पैठ बनाई है। इस चुनाव से कुछ महीने पहले भी राजग ने जमीनी हालात को भांपते हुए अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने में तत्परता दिखाई। राजग के दलों के बीच सीटों का सटीक बंटवारा हुआ। दूसरी ओर, विपक्षी खेमा अंत तक दुविधा से ग्रस्त दिखा। राजग में किसी तरह की फूट नहीं दिखाई दी तो महागठबंधन में कई सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' ने भी उसकी मुश्किलें बढ़ाने का ही काम किया, जो नतीजों में स्पष्ट रूप से नजर भी आया।

नेतृत्व का पहलू भी राजग के लिए निर्णायक साबित हुआ। राजग जहां प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उतरा था तो उसके

अवधेश राजपूत

सामने राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी थी। मोदी केंद्र सरकार के कामकाज और नीतीश राज्य सरकार के कामकाज को गिना रहे थे और उनके प्रचार का स्वरूप कुछ भिन्नता लिए हुए भी सुसंगति से परिपूर्ण था। दोनों ही नेता अपने-अपने राज्यों में लंबे अर्से तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मोदी कई वर्षों से देश की कमान संभाले हुए हैं तो नीतीश के पास भी केंद्र सरकार के कामकाज का अनुभव रहा है। कुल मिलाकर नेतृत्व क्षमता से लेकर अनुभव और गवर्नेंस के मामले में महारत से यह जोड़ी विपक्षियों पर बहुत भारी पड़ी। विपक्षी जोड़ी में राहुल वोट चोरी और अंबानी के यहां शादी में शिरकत जैसे मुद्दों को तूल दे रहे थे तो तेजस्वी बेरोजगारी और युवाओं को जोड़ने पर ध्यान देने में लगे थे। उनके प्रचार में तारतम्यता नहीं दिखी। तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने में भी आनाकानी की गई।

नीतीश की लोकप्रियता भी राजग के लिए वरदान साबित हुई। शुरुआत में मुख्यमंत्री को लेकर ऊहापोह के बाद चुनावों के बीच ही भाजपा के दिग्गजों द्वारा नीतीश की पैरवी गठबंधन के लिए उपयोगी साबित हुई। पिछली बार अलग चुनाव लड़कर चिराग पासवान ने राजग को क्षति पहुंचाई थी, लेकिन इस बार उन्हें भी चुनाव से पहले ही साध लिया गया। यही कारण है कि पांच साल पहले कड़ी टक्कर वाला चुनाव इस बार एकतरफा हो गया। राजद के साथ फिर कभी न जाने की बात को नीतीश द्वारा बार-बार दोहराने से भी उनके प्रति पालाबदल को लेकर खराब हुई धारणा कुछ सुधरी। जनता के मन को इस पहलू ने भी प्रभावित किया हो कि शायद यह नीतीश कुमार की सक्रियता वाला अंतिम चुनाव हो तो जिस व्यक्ति ने गर्त में जा रहे राज्य को फिर से प्रगति की ओर उन्मुख करने में अहम भूमिका निभाई हो, उसे एक शानदार जीत से एक यादगार विदाई भी दी जाए।

महिला मतदाता एक के बाद एक चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं। यह भी एक कारण है कि उन्हें ध्यान में रखकर घोषणाएं की जाने लगी हैं। बिहार चुनाव में भारी मतदान में भी महिलाओं का प्रमुख योगदान रहा। महिला मतदाताओं के बीच नीतीश की पैठ पहले से ही काफी मजबूत रही है। शराबबंदी की सबसे बड़ी समर्थक भी महिलाएं रही हैं। छात्राओं को साइकिल देने की पहल हो या जीविका दीदी जैसी योजना, उसने महिलाओं में नीतीश की लोकप्रियता बढ़ाई। इस कड़ी में चुनाव से पहले 10,000 रुपये की विशेष मदद और प्रदर्शन के आधार पर उसे दो लाख रुपये करने की घोषणा राजग के लिए सोने पर सुहागा जैसी साबित हुई।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिहार के जनादेश की छाप आगे विधानसभा चुनावों पर भी दिखेगी। बिहार के निकटवर्ती राज्यों बंगाल और असम में भाजपा का हौसला बढ़ेगा। ऐसी करारी हार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के साथ ही राजनीतिक मोलभाव की उसकी क्षमताएं घटाएगी। वह केरल और असम में अपने दम पर लड़ने की स्थिति में है। जबकि बंगाल और तमिलनाडु में उसे सहयोगियों के समर्थन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। बिहार के अनुभव से शायद ही उसे ज्यादा भाव मिले। कुछ समय के लिए जदयू के साथ से सत्ता के स्वाद को छोड़ दिया जाए तो पिछले 20 साल से राजद विपक्ष में ही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद को हार पहले भी मिली है, लेकिन इतनी तगड़ी हार के बाद न केवल पार्टी, बल्कि परिवार के भीतर भी उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगेंगे। आने वाले दिनों में राजद को अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च में फेलो हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-14

Jansatta Page No-6

Jansatta Page No-08

तकनीक के पैमाने पर महिला शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, लेकिन बदलते शैक्षिक एवं तकनीकी परिदृश्य के मद्देनजर आज भी महिला शिक्षा में व्यापक विकास एवं उन्नयन की महती आवश्यकता है। इस क्षेत्र में लैंगिक असमानता अभी भी गहरी पैठ बनाए हुए है।

प्रेरणा अवस्थी

महिलाओं की शिक्षा परिवार से लेकर राष्ट्र तक के विकास में अहम भूमिका निभाती है। हालांकि शिक्षा के पैमाने पर महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, लेकिन आज के बदलते शैक्षिक एवं तकनीकी परिदृश्य के मद्देनजर महिला शिक्षा में व्यापक विकास एवं उन्नयन की महती आवश्यकता है। यहां पर हाल ही की एक रपट का उल्लेख करना जरूरी होगा, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पूरे विश्व में लगभग 1.5 करोड़ लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। यह रपट महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम करने वाली संस्था 'संयुक्त राष्ट्र महिला' की ओर से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि हाल के दशकों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में लैंगिक समानता को लेकर काफी कुछ सुधार देखने को मिले हैं, मगर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें लैंगिक असमानता अभी भी गहरी पैठ बनाए हुए है।

अगर विद्यालयों में नामांकन की बात की जाए तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर महिलाओं की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। वहीं एक कड़वा सच यह भी है कि नामांकन कराने के बाद शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वालों में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। कई स्थानों पर तो 48.1 फीसद लड़कियां स्कूल जाने से वंचित हैं। अब अगर उच्च शिक्षा के परिदृश्य पर नजर डाली जाए, तो भी आंकड़े बहुत संतोषजनक नहीं है। यूनेस्को के वैश्विक शिक्षा निगरानी दल की ओर से किए गए खुलासे के अनुसार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 35 फीसद है। खास बात यह है कि पिछले दस वर्षों से यह आंकड़ा जस का तस बना हुआ है।

आज तकनीकी एवं डिजिटल क्रांति का युग है। डिजिटल क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों की वजह से आज शैक्षिक परिदृश्य भी हर स्तर पर परिवर्तित हो चुका है। लिहाजा, अब केवल शिक्षित होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से दक्ष होकर एवं कौशल विकास के पैमाने पर लगातार प्रगति करके ही खुद को इस बदलते परिदृश्य के साथ जोड़े रखा जा सकता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीक के नवीनतम उत्पाद दिन-प्रतिदिन उत्कृष्ट रूप ग्रहण करते जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव एक हद तक परिलक्षित होने लगा है। हाल की एक रपट के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2023 के बीच डेटा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 26 फीसद रही है।

संयुक्त राष्ट्र की महिला केंद्रित इकाई की रपट में बताया गया है कि महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा उचित रूप से उपलब्ध नहीं होने के पीछे एक बड़ा कारण सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। गौरतलब है कि हमारे सामाजिक परिदृश्य में लैंगिक असमानता एवं भेदभाव से परिपूर्ण सोच आज भी गहरे तक समाई हुई है। इसी सोच का दुष्परिणाम है कि लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती है। बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा के लिए विद्यालयों में नामांकन तो कर लेती हैं, मगर बीच में ही उन्हें मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसके प्रमुख कारणों में अल्प आयु में ही विवाह हो जाना और घरेलू कार्यों की आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारी लाद दिया जाना भी शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

की ओर से कराए गए एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है की बेटियों के स्कूल छोड़ने के पीछे एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक साधनों की कमी है। ऐसी लड़कियों की संख्या भी कम नहीं है, जो परिवहन संबंधी साधनों एवं अन्य सुविधाओं की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित हो जाती हैं।

> सरकार के स्तर से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' एवं अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वयन में लाई गई हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे सभी कितना सफल हैं, इस संबंध में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हम एक ओर विकसित राष्ट्र बनने का सपना एवं संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं लैंगिक असमानता एवं महिला अशिक्षा जैसी चुनौतियां भी एक कटु वास्तविकता के रूप में हमारे समक्ष खड़ी हैं। आज आवश्यकता है जल्द से जल्द इन चुनौतियों एवं बाधाओं से निजात पाने की, क्योंकि जब तक ये मौजूद रहेंगी, तब तक विकसित राष्ट्र बनने का स्वप्न कदापि साकार नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रपट बताती है कि 15 से 18 वर्ष की 39.4 फीसद लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। यही नहीं, 57 फीसद लड़कियां ग्यारहवीं कक्षा तक आते-आते पढ़ाई छोड़ देती हैं। पंद्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में 2.7 फीसद लड़कों की तुलना में 3.2 फीसद लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। एक अन्य रपट के अनुसार, विश्व के 68 फीसद देशों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित की शिक्षा को समर्थन देने वाली नीतियां मौजूद हैं, लेकिन इनमें से केवल पचास फीसद नीतियां ही महिलाओं की शिक्षा पर केंद्रित हैं। जाहिर है कि नीतिगत कमी अथवा नीतियों की विफलता भी महिला शिक्षा के अवरुद्ध होने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसके लिए बड़े एवं व्यापक स्तर पर प्रयासों की शृंखला को अमल में लाना होगा। इसमें पहला एवं सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास यह है कि व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र, प्रत्येक स्तर पर रूढ़िवादी सोच एवं अनावश्यक पूर्वाग्रहों से ग्रसित मानसिकता का जड़ से उन्मूलन करना होगा, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा में सबसे बड़ा बाधक तत्त्व यही है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के दृष्टिकोण से संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढांचे में पर्याप्त सुधार करने होंगे।

एक अन्य अहम पहलू यह भी है कि चूंकि आज आनलाइन शिक्षा एक विकसित रूप धारण कर चुकी है, इसलिए महिलाओं की डिजिटल साक्षरता पर शुरुआत से ही ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वे शिक्षा के नवीनतम स्वरूप एवं परिवेश में अपने आप को ढालने में समर्थ एवं सक्षम हो सकें। एक शिक्षित एवं सफल महिला केवल एक परिवार ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए आदर्श होती है। इस सोच के साथ शिक्षा की उन सभी कमियों को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए, जो विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करती हैं। भारत के संबंध में बात की जाए, तो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और वहां आज भी पुरुष प्रधान विचारधारा कहीं न कहीं हावी है। नतीजा यह होता है कि महिलाएं शिक्षा का विकल्प या तो चुन नहीं पातीं और यदि वे उस राह पर आगे बढ़ती भी हैं, तो बहुत आगे तक नहीं जा पातीं। इसके अलावा महिला असुरक्षा जो हमारे देश में एक बेहद ज्वलंत मुद्दा है, महिलाओं की शिक्षा में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। असुरक्षा के भय से बहुत से अभिभावक अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए बाहर भेजने से कतराते हैं।

हालांकि शासन के स्तर से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' एवं अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वयन में लाई गई हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे सभी कितना सफल हैं, इस संबंध में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हम एक ओर विकसित राष्ट्र बनने का सपना एवं संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर लैंगिक असमानता एवं महिला अशिक्षा जैसी चुनौतियां भी एक कटु वास्तविकता के रूप में हमारे समक्ष खड़ी हैं। आज आवश्यकता है जल्द से जल्द इन चुनौतियों एवं बाधाओं से निजात पाने की, क्योंकि जब तक ये मौजूद रहेंगी, तब तक विकसित राष्ट्र बनने का स्वप्न कदापि साकार नहीं हो सकता। शिक्षा आज केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह आनलाइन संसाधनों, आभासी मंच एवं डिजिटल माध्यमों तक विस्तृत हो चुकी है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति आज के युग की रीढ़ है। विश्व की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना तकनीकी विकास पर आधारित हो चुकी है। भारत जैसे विकासशील देश में विज्ञान एवं तकनीक को बढ़ावा देना राष्ट्र की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में यदि महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, तो देश की प्रगति को कई गुना गति मिल सकती है।

Jansatta Page No-6

Dainik Jagaran Page No-10

Jansatta Page No-6

संसाधनों की सीमा

संदीप कुमार सिंह

विकास की बेलगाम दौड़ में आज मनुष्य एक ऐसी स्थिति में आ खड़ा हुआ हुआ है, जहां आने वाले समय में उसके सामने खत्म होते प्राकृतिक संसाधनों का भीषण संकट उत्पन्न होने वाला है। यह संसाधनों के अति दोहन का ही परिणाम है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी अभावग्रस्त और संकटपूर्ण दुनिया सौंपने की कगार पर हैं, जिसमें कहीं जल संकट होगा तो कहीं प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से उपजी प्रकृति प्रदत्त समस्याएं, जैसे वनों के अतिदोहन से हुई पेड़ों की कमी और उसके परिणामस्वरूप मौसम और मानसून चक्र में परिवर्तन, नदियों का सूखना एवं दूषित होना, भूमि के दोहन से उपजी भूमि की उर्वरहीनता आदि।

इन सारी समस्याओं की जड़ में प्रमुख है, आवश्यकता से अधिक चीजों का उपयोग करना। यानी हम अपनी आवश्यकता को बिना सोचे-समझे ही अपने घर और जीवन में चीजों का अंबार लगाते जा रहे हैं। नतीजतन, संसाधनों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। कभी हमारे पास कुछ सीमित संख्या में कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि होते थे, आज हमारी आलमारियां, रसोई, कमरे सब भरे पड़े रहते हैं। फिर भी हमें जरूरत न होने पर भी चीजों को खरीदने में कोई हिचक नहीं होती। कभी रियायती प्रस्ताव वाले 'सेल' लगे होते हैं, कभी 'कैश बैक' के लालच में पड़कर और कभी दूसरों के पास किसी चीज को देखकर हम बस खरीदते ही रहते हैं। इस प्रकार, घर सामानों और कपड़ों से भर जाता है। प्रति व्यक्ति खपत न केवल संसाधनों पर दबाव बढ़ाता है, बल्कि उससे ग्रीनहाउस गैसों में भी वृद्धि होती है और अन्य पर्यावरणीय कारक भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> जब तक हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे और बिना सोचे-समझे केवल लोगों को देखकर या आकर्षक प्रस्ताव के लालच में पड़कर चीजें बटोरते रहेंगे, तब तक संसाधनों का उचित उपयोग संभव नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह इस भावना से काम करें कि 'विश्व का कल्याण हो'।

जब तक हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे और बिना सोचे-समझे केवल लोगों को देखकर या आकर्षक प्रस्ताव के लालच में पड़कर चीजें बटोरते रहेंगे, तब तक संसाधनों का उचित उपयोग संभव नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह इस भावना से काम करे कि 'विश्व का कल्याण हो'। हम इस विश्व के एक अंश के समान हैं और हमें अपने अंश के कर्तव्यों को समझना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा इस पृथ्वी के लिए जो कर्तव्य है, वह उचित तरीके से निर्वहन हो। हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सकते हैं। उसके लिए हमें मानासिक रूप से दृढ़ होना होगा। क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, उसमे भेद करके स्वयं को प्रशिक्षित करना होगा। आज के दौर में एक क्लिक पर सारी चीजें उपलब्ध हैं। यह आसानी से उपलब्ध होना ही कहीं हमें अतिभौतिकवादी तो नहीं बनाती जा रही है, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। खुद को रोकना होगा, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं एक अभावग्रस्त दुनिया छोड़ कर न जाएं। हमें यह भी धारण करना होगा कि हम अपने हिस्से के दायित्वों का अच्छी तरह से निवर्हन करें। कभी यह न सोचें कि एक मेरे ही जागरूक होने से क्या ही बदल जाएगा।

हमें जीवन के उन मूल्यों को भी समझना होगा, जिसमें चीजों के सीमित उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इस भाव को अपनाकर हम कम से कम में जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। हम इस भाव से भी मुक्त हो जाएंगे कि चीजों को बटोरने मात्र से ही जीवन सुखमय हो सकता है। आज मनुष्य एकाकी होता जा रहा है और चीजें उसका सहारा बनती जा रही हैं। इस तकनीकी युग में भौतिकवाद पहले से कहीं अधिक प्रबल है। समाज में दिखावे की भी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस दिखावे की प्रवृत्ति ही कहीं न कहीं चीजों को बटोरने की प्रवृत्ति का विकास कर रही है। पहले घरों में एक टेलीविजन होता था और पूरा परिवार साथ मिलकर देखता था, लेकिन आज हर घर में एक से अधिक टेलीविजन, हर हाथ में टीवी का काम करने वाले स्मार्टफोन, रेफ्रीजरेटर, कार आदि उपलब्ध हैं। इससे प्रति व्यक्ति खपत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे संसाधनो पर दबाव बढ़ रहा है। बाजारीकरण के इस दौर में लोक-लुभावन प्रचार हमारी खरीदने की प्रवृत्ति में आग में घी का काम कर रहे हैं। कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए अनेक हथकंडे भी अपनाती हैं, जिसमें एक के साथ एक मुफ्त, 'कैश बैक', कीमतों में कमी आदि। इस तरह के विज्ञापनों को देखकर हम आकर्षित होकर आवश्यकता न होने पर भी खरीदना शुरू कर देते हैं। इस तरह न केवल हमारा बजट बिगड़ता है, बल्कि अनावश्यक चीजों से घर भी भर जाता है। उपयोगिता भूलकर हम विज्ञापनों के झांसे में आकर लगातार बाजारीकरण और विज्ञापनों का शिकार होते रहते हैं।

आज आवश्यकता है कि हर एक इंसान संसाधनों के दोहन के प्रति जागरूक हो। जब हम अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तभी हम एक स्वच्छ और टिकाऊ विश्व की अवधारणा को साकार होते देख सकने के साक्षी होंगे। इसके साथ ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी दुनिया छोड़ सकेंगे, जहां उनके सामने प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं होगी। भावी पीढ़ियां भी सबक लेकर प्रकृति के प्रति अपने संबंधों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगी। इस प्रकार तेजी से क्षय होते प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लंबे समय तक मानव समाज स्वयं के लिए कर सकने में सक्षम होगा। संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बने रहने से उसके दाम में भी स्थिरता बनी रहेगी और यह समाज के निचले और कम आय वाले तबके के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

भविष्य से खिलवाड़

भारत में कुशल पेशेवर विदेश में नौकरी तलाशने को प्राथमिकता देते हैं। अच्छा वेतन पाने की ख्वाहिश उन्हें विदेश खींच ले जाती है। इस मामले में अमेरिका भले ही भारतीयों की पहली पसंद है, मगर अब वहां ठिकाना बनाना आसान नहीं रह गया है। अमेरिका ने इस साल सितंबर में पहले एच-1बी वीजा पर शुल्क कई गुना बढ़ा दिया और अब नई नीति तैयार की गई है, जिसके तहत किसी भी देश से अमेरिका जाने वाले पेशेवरों की नौकरी वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित करने तक ही सीमित रहेगी, इसके बाद उन्हें स्वदेश वापस भेज दिया जाएगा। यानी अमेरिका अब विदेशी प्रतिभाओं का इस्तेमाल केवल अपने कर्मियों का हित साधने तक ही करेगा। गौरतलब है कि अमेरिका के वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने गुरुवार को कहा कि एच-1बी वीजा के तहत कुशल विदेशी पेशेवरों को लाने का मकसद अमेरिकी कर्मियों को उस कौशल में प्रशिक्षित करना है, जो उनके पास नहीं है। प्रशिक्षण में तीन से सात साल लगेंगे, इसके बाद वे स्वदेश लौट जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि भारत समेत अन्य देशों के लोग अब अमेरिका में स्थायी तौर पर नौकरी नहीं कर पाएंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को फिर से महान बनाने का दावा करते रहे हैं। उनका कहना है कि विदेशी पेशेवरों के बड़ी संख्या में आने से वहां के नागरिकों का रोजगार छिन रहा है। इसी क्रम में उन्होंने अमेरिकी कंपनियों पर अपनी विनिर्माण इकाइयों को अन्य देशों से स्वदेश वापस लाने का दबाव भी बनाया था। अमेरिका ने एच-1बी वीजा का शुल्क भी इसलिए बढ़ाया है, ताकि इसकी पहुंच केवल उच्च कौशल वाले विदेशियों तक ही सीमित रहे। हाल की एक रपट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में दो लाख से ज्यादा भारतीयों ने एच1-बी वीजा हासिल किया था। वर्ष 2020 से 2023 के बीच कुल स्वीकृत वीजा में 73.7 फीसद भारतीयों को मिले थे। खासकर भारतीय आइटी कंपनियां अमेरिकी बाजार पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में सवाल है कि एच1-बी वीजा को लेकर अमेरिका की नई नीति का लक्ष्य क्या विदेशी प्रतिभाओं को सिर्फ अपने फायदे भर के लिए इस्तेमाल करने जैसा नहीं है? इसे विदेशी पेशेवरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या कहा जाएगा?

नतीजों का संदेश

बिहार में विधानसभा के लिए हुए चुनावों के नतीजे निश्चित तौर पर वहां की जनता का फैसला है, लेकिन हार-जीत के जैसे आंकड़े सामने आए, उसकी उम्मीद कम से कम वहां के विपक्षी दलों को बिल्कुल नहीं रही होगी। दो चरणों में हुए मतदान के बाद शुक्रवार को हुई मतगणना में न केवल सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भारी जीत मिली, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी मैदान में मुकाबला एकतरफा था। हालांकि प्रचार के दौरान विपक्षी महागठबंधन को जैसा समर्थन मिलता दिखा था, उससे यही लगा कि चुनावी मुकाबला एकतरफा साबित नहीं होने वाला है और राजद-कांग्रेस तथा अन्य सहयोगी दलों का महागठबंधन चुनाव में राजग को एक मजबूत चुनौती देने वाला है। मगर अब आए नतीजों से यह साफ है कि बिहार के चुनावी मैदान में मतदाताओं को आकर्षित करने और उनका मत हासिल करने के मामले में सत्ताधारी गठबंधन के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। दूसरी ओर, विपक्ष की राजनीति और विधानसभा चुनावों में जीत के लिए किए गए प्रयासों के लिहाज से देखें तो ये नतीजे उनके लिए अप्रत्याशित हैं, क्योंकि प्रचार के दौरान सभाओं और रैलियों में उन्हें लोगों का जैसा व्यापक समर्थन मिलता दिखा था, वह शायद वोट में तब्दील नहीं हो सका।

सवाल है कि विपक्ष की राजनीति के महारथी जनता के बीच दिखने वाले समर्थन के बरक्स जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाने में नाकाम क्यों हुए! माना जा रहा है कि राज्य के मतदाताओं के सामने अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से जो कुछ तात्कालिक लाभ के मुद्दे सामने रखे गए, लोगों ने उसी में से चुनाव के लिए अपनी प्राथमिकता तय की। मसलन, एक ओर बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में तत्काल दस हजार रुपए भेजने की व्यवस्था की, तो दूसरी ओर, महागठबंधन ने हर परिवार के लिए सरकारी नौकरी सहित कई अन्य वादे किए। ऐसा लगता है कि राज्य के लोगों की राय पर भविष्य के लिए किए गए वादों के बजाय महिलाओं को तुरंत मिली आर्थिक राहत का मुद्दा ज्यादा भारी पड़ा और उसने चुनाव में मतदान के रुख को तय करने में एक प्रमुख कारक के रूप में काम किया। राजद और उसके सहयोगी दल शायद जनता को यह भरोसा दिला पाने में कामयाब नहीं हो सके कि सरकार बनने पर उनके वादे वास्तव में जमीन पर उतर सकेंगे।

इसके अलावा, बिहार में इस बार मतदान का जैसा आंकड़ा सामने आया, वह भी चौंकाने वाला था। जब दोनों चरणों में लगभग सड़सठ फीसद वोट पड़े, तब स्वाभाविक रूप से ऐसे आकलन सामने आने लगे कि इतना मतदान फीसद आमतौर पर सत्ता विरोधी लहर का संकेत देते हैं। मगर अब जैसे नतीजे सामने आए हैं, उसमें ज्यादा मत पड़ने के साथ जुड़ी सत्ता विरोधी लहर की धारणा एक तरह से खारिज होती दिखी। अब बिहार के मतदाताओं ने एक बार फिर से राजग सरकार के कामकाज और उससे पैदा उम्मीदों को अपना भारी समर्थन दिया है, वहीं विपक्षी दलों और खासतौर पर राजद के सामने आने वाले दिनों में अपनी पार्टी के मजबूत दखल को बचा पाने तक की चुनौती सामने होगी। मगर उम्मीद की जानी चाहिए कि स्पष्ट बहुमत के साथ बनने वाली सरकार के कामकाज आम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रख कर संचालित होंगे और राजनीतिक मोर्चे पर राज्य में लोकतंत्र का जीवन पहले से ज्यादा बेहतर होगा।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों और देशों की सांस्कृतिक झलक

अनामिका सिंह
नई दिल्ली, 14 नवंबर।

भारत मंडपम में लगने वाले 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार पर्यटकों को कई राज्यों के इतिहास से रूबरू होने का मौका भी मिलने वाला है। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' विषय पर सभी राज्यों ने अपने मंडपों को तैयार किया है। यहां दिल्ली मंडप में जहां आपको लाल किला की प्राचीर और इंडिया गेट देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान मंडप में चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय दुर्ग व जयपुर के जंतर-मंतर को देखा जा सकेगा। इसके अलावा, महाराष्ट्र मंडप के प्रवेश द्वार पर शिवाजी की वीरता को दिखाया गया है।

बता दें कि बिहार मंडप का प्रवेश द्वार सीतामढ़ी में बन रहे पुनारौधा सीता माता मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है जबकि अंदर बिहार संग्रहालय से लाए गए पुरावशेषों की प्रतिकृतियों को लगाया गया है। झारखंड मंडप के प्रवेश द्वार पर बिरसा मुंडा को उनके सहयोगियों के साथ तीर-धनुष लिए प्रतिमा से सजाया गया है। वहीं बात अगर देशों की करें तो थाइलैंड इस साल अपने 'नेचुरल वाटर पर्ल' से बने गहनों को लेकर मेले में शिरकत कर रहा है। जबकि ईरान बकलावा मिठाई को लेकर आया है, जिसके एक पीस का दाम 100 रुपए रखा गया है। अगर बात ईरानी पिस्ता चाकलेट की करें तो एक हजार रुपए की एक है। इसके अलावा ईरान बड़े-बड़े सजावटी सामानों को लेकर आया है जो बेहद आकर्षक हैं। इनमें बड़े-छोटे फूलदान, फव्वारे, घंटिया, दवा पीसने की ओखली व अन्य सामान हैं जोकि गोमेद पत्थर से बनाए गए हैं। बता दें कि मेले का उद्घाटन शुक्रवार शाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने किया। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंडप का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश मंडप में इस वर्ष 140 स्टाल लगाए गए हैं, जिसमें राज्य के चमड़ा, बर्तन, वस्त्र, हस्तशिल्प व कृषि उद्योग को प्रदर्शित किया है।

मुख्यमंत्री ने किया दिल्ली मंडप का उद्घाटन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को हाल नंबर-2 में बने दिल्ली मंडप का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न स्टालों पर गईं और दिल्ली की महिला उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स व अन्य उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वो दिल्ली मंडप में जरूर आएं और दिल्ली की महिला उद्यमियों और स्थानीय कलाकारों का उत्साहवर्धन करें।

बस्ते के बोझ से छिनता बचपन

पूरे देश में आज बाल दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह दिन केवल बच्चों का त्योहार नहीं, बल्कि बचपन की मासूमियत, उत्साह और उज्ज्वल भविष्य का उत्सव है। यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें बच्चों से अत्यधिक स्नेह था और बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बाल दिवस केवल एक अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, बच्चों को प्यार, मार्गदर्शन और प्रेरणा देने की। हमें उन्हें एक ऐसा माहौल देना चाहिए जहां वे अपनी कल्पनाओं को पंख दे सकें, गलतियों से सीख सकें और आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकें। बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि बच्चे हमारे समाज की नींव हैं। उनके सपनों और विचारों को सम्मान देना, उन्हें सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण देना हमारा दायित्व है। पंडित नेहरू मानते थे कि आज के बच्चे कल का भारत हैं। और हम सभी कहते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं इसीलिए यह दिन बच्चों की रचनात्मकता, ऊर्जा और शिक्षा के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। बस्ते का भारी बोझ और देर रहे होमवर्क के कारण बच्चों का बचपन छीन रहा है, क्योंकि इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बरा असर पड़ता है, खेलने-कूदने का समय नहीं मिलता और वे चिड़चिड़े हो जाते हैं।

राजेश मणि

इस वजह से बच्चों में पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं और वे सामान्य विकास से वंचित रह जाते हैं। विद्यालयों में होमवर्क का इतना अधिक दबाव रहता है कि छात्र खेलकूद में शामिल नहीं हो पाते। लिहाजा इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इस भागदौड़ में उनका बचपन कहां खो जाता है, उन्हें भी पता नहीं चलता और धीरे-धीरे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन होता दिखता है। और वे बचपन से सीधे एक दबे हुए किशोर में परिवर्तित हो जाते हैं. भविष्य में देश के विकास का बोझ वहन करने वाले अबोध नौनिहाल आज अपने बस्ते के बोझ से दबे जा रहे हैं। 20 किलो के बच्चे और 10 से 12 किलो का उनका बैग, यह उन पर जुल्म नहीं तो और क्या है? आज की शिक्षा प्रणाली में इनका बचपन कुंठित हो रहा है और शारीरिक और मानसिक विकास ठप पड़ता जा रहा है।

शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण अब निजी विद्यालयों के द्वारा अधिक से अधिक पुस्तक देना उत्कृष्टता का पैमाना बनता जा रहा है।इन विद्यालयों के द्वारा छोटी कक्षाओं के लिए भी दर्जनों पुस्तकें दी जाती हैं, उसके साथ अलग-अलग विषयों की अलग-अलग कापियां। लंच बॉक्स, पानी की बोतल और छाता से वजन और भी बढ़ जाता है.इतना अधिक वजन कई बीमारियों का जनक हो सकता है, इसका ख्याल स्कूल प्रबंधन कतई नहीं करते। विशेष रूप से बढ़ते हुए बच्चों में कैल्शियम की कमी और इतने वजन के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। कई बीमारियां पनपने लगती हैं. चिकित्सकों की माने तो बच्चे अब कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझने लगे हैं। कितनों के आंखों पर तो पावर वाले चश्मे भी चढ़ गये हैं। इतनी कम उम्र में इतने बड़े कर्तव्य का बोध कराना अब उन्हें अवसाद की स्थिति में लाने लगा है। नस और हड्डी से संबंधित बीमारियों भी बच्चों में होने लगी है। इस संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक बताते हैं कि मानसिक दबाव के कारण बच्चों में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही अधिक वजन से बैकपेन, रीढ़ में कमजोरी, नेकपेन तथा नस से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं।

कान्वेंट स्कूलों में छोटी कक्षा के मासूमों व दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के बराबर होमवर्क दिया जा रहा है जिससे देर रात तक इन छात्रों को सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती, खेलना किसने देखा। बच्चे स्कूल से घर आकर न तो कुछ वक्त फुर्सत के निकाल पाते हैं और न ही खेलों के लिए उचित समय मिल पा रहा है। बढ़ी स्पर्धा के दौर में सरकारी स्कूलों को छोड़कर अभिभावक अपने नौनिहालों को भेजकर शिक्षा दिलाने के लिए निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान ने इस दिशा में प्रयास किए, परंतु उनके अनुपालन का कार्य केवल सैद्धांतिक स्तर तक सीमित रहा, इसको व्यावहारिक रूप नहीं मिल पाया। हमें कुछ ऐसे उपाय सोचने चाहिए, जिससे ये मासूम बस्ते के बोझ से मुक्त हो सकें और उनका स्वाभाविक विकास हो। इसलिए आवश्यक है। निश्चय ही कुछ स्वार्थी तत्व इन महकते फूलों पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आते। उनका उद्देश्य हर कक्षा में अधिक से अधिक पुस्तकें लगवाना रहता है, जिससे वे पुस्तक विक्रेताओं और दुकानदारों से कमीशन लेकर अपनी जेब गर्म कर सकें। दूसरी बात जो ध्यान में देनी है, वह यह है कि कक्षा के बंद कमरे में पाठ रटवाने के स्थान पर उन्हें रोचक ढंग से पढ़ाया जाए। विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा पुस्तकों के भार से दबी है। इस बोझ को कम करने की काफी चर्चा और सुझाव आते रहे, परंतु वे क्रियात्मक रूप से कुछ अधिक सफल नहीं हो पाए। बच्चों के दिमाग में शब्दों को भरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके मस्तिष्क में शब्दों को निकलवाना चाहिए। वे अच्छी तरह से शब्दों को समझें, रटें नहीं। बच्चों को व्यावहारिक विद्या सिखलाई जानी चाहिए, ताकि उनके विचार शक्ति में इजाफा हो

डिजिटल युग में आज बच्चों की मनोवृत्ती भी बदल गई है। परिस्थितिवश खेल कूद और अन्य गतिविधियों से उनका मोह भंग हो गया है। मैदानी अभिरुचि का स्थान किताबों और पांडिकता ने ले लिया है। मोबाइल और कम्प्यूटर भी आधुनिक शिक्षा के पर्याय बनते जा रहे हैं। सामान्य या विषयगत शिक्षण के अलावा इन विषयों की पुस्तकों का बोझ भी बढ़ा ही है। नर्सरी और घर में भी मिल रहे इस ज्ञान का ही प्रतिफल है कि आज दो-तीन साल का बच्चा भी आप हमसे ज्यादा अच्छे से मोबाइल को संचालित करता है। मोबाईल के गेम उसे भाते हैं। इसे देख हम भी हर्षित तो होते ही हैं और जब तब दूसरों के सामने इसका गुणगान भी करते रहते हैं। यही प्रशंसा उन्हें अन्य गतिविधियों और मैदानी खेल कूद से दूर करती है।

शहरों में जब रहने के ठिकाने ही छोटे हो गए हों तो आसपास खेल की सुविधाओं की बात करना भी बेमानी ही है, जिससे बच्चे घर में ही कैद से हो गए हैं। अलावा इसके एक बड़ा कारण निरंतर घटित हो रही असामाजिक गतिविधियां भी हैं, जिसने सबको अपने बच्चों के प्रति इतना सजग या भयभीत कर दिया है कि वे उसे अकेले बाहर जाने ही नहीं देते। ऐसे में बच्चे सीमित दायरे में कैद हो गए हैं। घर से स्कूल और स्कूल से घर ही उनकी दिनचर्या हो गई है। रही कही कसर कोचिंग क्लासेस ने पूरी कर दी है। अव्वलता प्राप्त करने की होड़ या भय ने उन्हें ग्रसित कर मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है जो चिन्ताजनक है।

स्कूलों की बात करें तो हम अपने बच्चों के लिए अधिकतर प्राइवेट स्कूलों को ही पसंद करते हैं, जिन्हें केवल अपना व्यवसाय चलाना होता है। यहां का अलग-अलग पाठ्यक्रम और बढ़ती किताबें भी बस्तों का बोझ बढ़ाती हैं। इन स्कूलों में अन्य गतिविधियां होती जरूर हैं पर वे भी नफा-नुकसान पर ही आधारित होती हैं। आज भी इस देश में करोड़ों बच्चे बाल श्रमिक हैं। जो चाय की दुकानों पर नौकरों के रूप में, फैक्ट्रियों में मजदूरों के रूप में या फिर सड़कों पर भटकते भिखारी के रूप में नजर आ ही जाते हैं। इनमें से कुछेक ही बच्चे ऐसे हैं, जिनका उदाहरण देकर हमारी सरकार सीना ठोककर देश की प्रगति के दावे को सच होता बताती है। यही नहीं आज देश के बच्चे शोषण के शिकार भी हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे अपने रिश्तेदारों या मित्रों के यौन शोषण का शिकार हैं। अपने अभिभावकों के प्रति अनभिज्ञता व अज्ञानता के कारण ये बच्चे शोषण का शिकार होकर जाने-अनजाने कई अपराधों में लिप्त होकर अपने भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं।बचपन आज भी भोला और भावुक ही होता है लेकिन हम उन पर ऐसे-ऐसे तनाव और दबाव का बोझ डाल रहे हैं कि वे कुम्हला रहे हैं। उनकी खनकती-खिलखिलाती किलकारियां बरकरार रहे इसके ईमानदार प्रयास हमें ही तो करने है। देश के ये गुलाबी नवांकुर कोमल बचपन की पांखें सहेजें, इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें कठोर और क्रूर नहीं बल्कि मयूरपंख सा लहलहाता बचपन दें।

जरीब...जरीब...जरीब... क्या है ये जरीब...

आइये आज आपको जानकारी देते है एक ऐतिहासिक व दुर्लभतम वस्तु की.... दसकों से देस में बंदोबस्ती की मांग चली आ रही है। देश की आज़ादी के बाद 1960 में बंदोबस्ती हुई थी। तब से लेकर आज तक अपने देश मे जमीन को लेकर बंदोबस्ती की मांग चली आ रही है, क्योंकि कई तरह के जमीनी विवाद , कब्जो आदि की समस्याओं का एकमात्र हल है बंदोबस्ती। अपने देश के ज्यादातर लोग बंदोबस्ती के बारे में तो जानते है, लेकिन बंदोबस्ती कैसे होती है ,और बंदोबस्ती में जमीन की नाप छाप किस चीज से की जाती है। इसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान होंगे मेरी तरह। 8 फरवरी 2019 को वीरपुर डुंडा पटवारी चौकी गया तो वहां एक बहुत ही अजीब और दुर्लभ वस्तु नजर आई।

जिज्ञासावश मैंने जानकारी चाही तो मालूम हुवा कि ये लोहे की पतली संगल (जंजीर) की तरह नजर आने वाली वस्तु अति दुर्लभ तो है ही उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। ये अलग बात है कि इसके बारे में व इसके इस्तेमाल व इसका उपयोग कैसे किया जाता है दोनों के बारे में जानकारी रखने वाले लोग अब शायद ही बिरले बचे होंगे। ये लोहे की बनी जंजीर 1960 से पहले की है।। क्योंकि इसका उपयोग वर्ष 1960 में जमीन के बंदोबस्ती में किया गया था, और इसका नाम है ,,,जरीब,,, जरीब क्या है ? आपको आगे की जानकारी बताते है। जरीब लम्बाई नापने की एक इकाई है, साथ ही जिस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है उसे भी जरीब कहते है। एक जरीब की मानक लम्बाई 66 फीट अथवा 22 गज अथवा 4 लट्ठे (Rods) होती है।

जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती है, इस प्रकार प्रत्येक कड़ी की लम्बाई 0.6 फ़ुट या 7.92 इंच होती है। 10 जरीब की दूरी 1 फर्लांग के बराबर और 80 जरीब की दूरी 1 मील के बराबर होती है। जरीब, लोहे की कड़ियों की बनी होती है और इसके दोनों सिरों पर पीतल के हैडल बने होते है। इंग्लैण्ड में जरीब (चेन) का निर्माण सर्वेक्षक और खगोलशास्त्री एडमंड गुंटर ने 1620 में किया। भारत में इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ स्पष्ट नहीं पता है। आम तौर पर इसके आविष्कार का श्रेय राजा टोडरमल(अकबर के दीवान) को दिया जाता है। जिन्होंने 1570 के बाद भूमापन के क्षेत्र में कई सुधार किये। इससे पूर्व शेरशाह के ज़माने में जमीन नापने के लिए जो जरीब प्रयोग में लाई जाती थी वो रस्सी की बनी होती थी और इससे माप में काफी त्रुटियाँ आती थी। टोडरमल ने इसकी जगह बाँस के डंडों की बनी कड़ियों की बनी जरीब का प्रयोग शुरू किया। जिसे वर्तमान अर्थों में पहली जरीब (जंजीर या चेन) कहा जा सकता है। इस जरीब की लम्बाई 60 इलाही गज होती थी और 3600 इलाही गज (1 ×1 जरीब का रक़बा) एक बीघा कहलाया।

दक्कन में शिवाजी ने रस्सी के माप की जगह, काठी (डंडा या लट्ठा) द्वारा माप की पद्धति अपनाया था और मलिक अम्बर ने पहली बार जरीब (बांस वाली जंजीर) का प्रयोग शुरू करवाया। 66 फ़ीट लम्बाई वाली आम जरीब, जिसे गुण्टर्स जरीब भी कहते है, के आलावा अन्य कई प्रकार की जरीबें भी विविध कार्यों अनुसार प्रयोग में लाई जाती है।

हिन्दी भाषा की उन्नति में बिहार के साहित्यसेवियों का अवदान

अनिल सुलभ

हिन्दी भाषा का जो स्वरूप हम आज देखते हैं,जिसे आधुनिक हिन्दी भी कहा जा सकता है,और जिसे खड़ी बोली भी कहा गया है, मेरी दृष्टि में संसार की नवीनतम भाषा है। आधुनिक हिन्दी की आयु को अभी दो सौ वर्ष भी नही हुए। इसके पूर्व की श्हिन्दीश वस्तुतः हिन्दी-पट्टी के रूप में चिन्हित किए गए, उत्तर भारत के अविभाजित प्रदेशों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली पंजाब, हरियाणा आदि में बोली जाने वाली लोक-भाषाओं को माना गया है, जिनमें, ब्रज, अबधी, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, मैथिली, डोंगरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, मारवाड़ी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाएँ सम्मिलित हैं। सुर, तुलसी, कबीर, रहीम, रसखान, विद्यापति, सरहपा आदि संत कवियों, बिहारी जैसे ऋंगार के महान कवियों की भाषा ये ही लोक-भाषाएँ य ब्रज, अबधी, मैथिली आदि थी, जिन्हें हिन्दी माना गया है। यदि आज की हिन्दी के साथ, इनकी तुलना की जाए तो ये लोक-भाषाएँ सर्वथा भिन्न प्रतीत होंगी। किंतु इसकी अखिल भारतीय तथा वैश्विक पहचान, विद्यापति, तुलसी, सुर, कबीर, रहीम, रसखान आदि की उन्हीं कालजयी तियों से है, जो इसकी पूर्वजा लोक-भाषाओं में लिखी गई।

इसके पूर्व बौद्ध-साहित्य में हम हिन्दी का प्राचीन स्वरूप देख सकते हैं, जिन्हें हम प्रात, पाली और अपभ्रंश भाषाओं में पाते हैं। ये भाषाएँ, तबके विशाल मगध राज्य की भाषाएँ थीं। कालांतर में ये मागधी, आज जिसे मगही कहा जाता है, में रूपांतरित हो गईं। इस पृष्ठभूमि के साथ जब हम हिन्दी भाषा की उन्नति में बिहार के साहित्यकारों के अवदान पर विचार करते हैं, तो हमारा हृदय गौरव के पुलकनकारी अनुभूतियों से भर जाता है। समस्त प्राचीन बौद्ध-साहित्य, बिहार के साहित्यकारों के विराट अवदान से भरे पड़े हैं। हिन्दी साहित्य के भक्ति-काल में, जिसे इसकी पूर्वजा लोकभाषाओं के स्वर्णिम-काल के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, उस संत-साहित्य की परंपरा में सरहापा का नाम अवश्य ही जुड़ जाता है, जो बिहार के थे। उसी महान परंपरा के पुरोधाओं में कवि-कोकिल विद्यापति का नाम स्वतः स्मरण होता है, जिन्होंने मैथिली भाषा की अनन्य मिठास से, संसार को अवगत कराया। विद्यापति के लोक-संस्कार-गीत हमारी लोक-संस्कृति की अनमोल धरोहर हैं। बाद के काल में भोजपुरी के महान कवि भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र आदि कवियों को भी हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर हम ये पाते हैं कि, हिन्दी भाषा की उन्नति में आदि काल से ही बिहार के साहित्यकारों का अवदान सर्वाधिक महवपूर्ण रहा है।

आधुनिक हिन्दी की भी बात करें तो, इसकी पहली कहानी लिखे जाने का श्रेय भी बिहार को जाता है। विद्वानों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि, भोजपुर के कथाकार श्री सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक खड़ी बोली हिन्दी की पहली कहानी लिखी थी, जो ईसवी सन के आस-पास लिखी गई थी। यह खड़ी बोली की बाल्यावस्था थी। यह वही काल था, जब महान साहित्यसेवी भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं तत्कालीन साहित्य-सेवियों ने हिन्दी के नए रूप को गढ़ना आरंभ किया था। इसीलिए हिन्दी साहित्य के इतिहास के इस युग को भारतेंदु-युग के रूप में स्मरण किया जाता है। विद्वानों की मान्यता है कि, यह भारतेंदु ही थे, जिन्होंने खड़ी बोली को अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया था। उसी दौर में बिहार के साहित्य-सेवी भी अपना महवपूर्ण योगदान दे रहे थे।

कहलगाँव, भागलपुर के संत-कवि सरहपा बौद्ध-दर्शन के महान विद्वान और महाकवि थे। उनकी कविताओं में आज की खड़ी बोली के प्रयोग मिलते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक हिन्दी की पहली कविता का श्रेय भी बिहार को ही जाता है। आगे चलकर बिहार के अनेक स्वनामधन्य साहित्यकारों ने आधुनिक हिन्दी की नींव पुख्ता की। उनमें, भोजपुर के श्री विजयानंद त्रिपाठी श्री कवि, बगहा (पश्चिमी चंपारण) के पं चंद्रशेखरधर मिश्र, भोजपुर के ही श्री शिवनंदन सहाय, हिन्दी-साहित्य में रहस्य-रोमांच और तिलिस्म के जनक और चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति के महान लेखक बाबू देवकी नंदन खत्री जैसे विद्वान लेखकों और कवियों के नाम आदर से लिए जा सकते हैं। नवीन बिहार के स्वपन-द्रष्टा के रूप में वंदित महेश नारायण, जो अंग्रेजी और हिन्दी में समान अधिकार से लिखते थे,अत्यंत प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। किंतु स्वतंत्रता-संग्राम में, राजनैतिक संघर्ष के कारण साहित्य-सेवा को अपेक्षित समय नहीं दे पाए। जिस प्रकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु और अद्‌भुत काव्य-चेतना के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की साहित्यिक प्रतिभा राजनीति के प्रस्तर के नीचे दब गई, उसी तरह, महेश नारायण की साहित्यिक प्रतिभा का अपेक्षित लाभ साहित्य-संसार को नही मिल सका। यदि ये दोनों विद्वान राजनीति में नहीं होते, तो साहित्य-संसार के बड़े नक्षत्र सिद्ध होते। महेश बाबू को मुक्त-छंद की प्रथम कविता लिखने का श्रेय जाता है।

National Sahara Page No-6

ऋण के जाल में फंसे देशों से भारत के राज्यों को मिलती है सीख

वैश्विक स्तर पर कई विकासशील एवं अविकसित देशों पर लगातार बढ़ रहे ऋण के दबाव के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। इन देशों द्वारा अपने नागरिकों को लम्बे समय तक मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा गया है एवं यहां की सरकारों द्वारा अपने आय के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऋण लेकर भी जारी रखना अब इन देशों के लिए आत्मघाती निर्णय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज यह देश दिवालिया होने के मुहाने पर खड़े हैं तथा इन्हें अपना सामान्य प्रशासन चलाने के लिए खर्च करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृति, अधिक ब्याज दर, आय में कम वृद्धि होना, आदि कारकों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं परंतु, उन्हें अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च लगातार बढ़ाते रहना होते हैं। इन्हीं कारणों के चलते श्रीलंका, अर्जेंटीना, सूडान, ग्रीस, मालदीव, सेनेगल, आदि देशों में तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्यथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल हैं - जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221.5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)। ग्रीस, घाना, हैती, मोजांबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डवांडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा में वित्तीय संकट खड़ा हो गया था एवं उस समय पर युगांडा अपने सामान्य खर्चों को जारी रखने के स्थिति में भी नहीं था। भारत में भी कुछ राज्य हूफ्रीबीह्न के नाम पर कुछ ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनके अंतर्गत राज्य की जनता के बिजली एवं पानी के बिल समय समय पर माफ किये जा रहे हैं। किसानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति के बैंक खातों में सीधे ही कुछ राशि प्रति माह जमा की रही है। जबकि, इन राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनके बजट इस अतिरिक्त खर्च को वहन कर

सकें। कुछ राज्य तो आज मजबूरी में इन योजनाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेने लगे हैं। जिसका प्रभाव इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत रूप से पड़ रहा है। यदि समय पर ये राज्य नहीं चेते एवं इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो ये राज्य अपने भारी भरकम ऋणों पर ब्याज अदा करने में चूक करने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राज्यों की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और इन राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। लोकलुभावन राजनीति इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु और सवाल खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से पंजाब, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही के समय में पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की वित्तीय सेहत बहुत बिगड़ी है। सभी राज्यों की वित्तीय सेहत का विस्तार से आकलन करने पर ध्यान में आता है कि कई राज्यों द्वारा अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं, लोकलुभावन घोषणाओं, अत्यधिक सब्सिडी देने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाली से इन राज्यों की वित्तीय सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है। राज्य, विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, कई लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं जैसे कि बिजली एवं पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा, उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का वादा आदि जिसका सीधा असर राज्य की माली हालत पर पड़ता है। पंजाब की आर्थिक स्थिति पूर्व में ही बहुत गम्भीर अवस्था में पहुंच चुकी है फिर वहां नई सरकार ने किए गए चुनावी वादे अर्थात मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे पंजाब की स्थिति निश्चित रूप से और अधिक बिगड़ने जा रही है और पंजाब को ऋण की किस्त एवं ऋणों पर ब्याज अदा करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। किन परिस्थितियों में, कितने प्रकार की, कितनी और किस स्तर तक लोकलुभावन घोषणाएं की जानी चाहिए, इस सम्बंध में अब नियम बनाने का समय आ गया है। वैसे यदि ऋण को उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय तो अधिक ऋण-सकल घरेलू अनुपात अपने आप में बुराई नहीं है परंतु जब ऋण लेकर इसे अनुत्पादक कार्यों जैसे मुफ्त बिजली एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराने जैसे कार्यों पर खर्च किया जाता है तो इसका राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चुनावों के वादे पूरे करने के लिए राज्यों द्वारा ऋण लिए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते पंजाब की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई हैं। देश के कई राज्य आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि इन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद यदि समय पर नहीं पहुंचाई जाती तो इन राज्यों की स्थिति भी आर्जेंटीना, श्रीलंका अथवा ग्रीस जैसी बनती दिखाई देती। कुछ राज्यों की स्थिति तो यह है कि इनके रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उनकी कुल आय का 90 प्रतिशत भाग इन खर्चों पर उपयोग हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के विकास कार्यों पर खर्च करने को कुछ बचता ही नहीं है। अब इन राज्यों की आय कैसे बढ़े? इन राज्यों द्वारा लगातार की जा रही लोक लुभावन घोषणाओं के कारण इन राज्यों के खर्चे लगातार अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के खर्चों को करने के लिए नित नए ऋण लिए जा रहे हैं और इन ऋण राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पाने के कारण ये राज्य अपनी आय में वृद्धि भी नहीं कर पा ररही हैं। इस प्रकार ये राज्य ह्रडेट ट्रैपह्न की स्थिति में फंसते जा रहे हैं। आय का 25 से 30 प्रतिशत भाग ऋण का ब्याज भुगतान करने में ही खर्च हो रहा है। पंजाब तो अब आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। इसी तरह राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की स्थिति भी बिगड़ रही है। अगर राज्य पुंजीगत खर्च नहीं कर रहे हैं तो अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। इस प्रकार तो भविष्य में इन राज्यों की विकास दर भी रुक जाने वाली है। विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय। जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 330 यूनिट बिजली मुफ़्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं। यदि राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है तो इसका खामियाजा भी अंततः उस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। यह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आदि मदों पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। राज्य में आर्थिक विकास की गति कम होने से इन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे है।

Dainik Ujala Page No-6

आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल

भारत विविध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन-पद्धतियों वाला समृद्ध देश है, और इसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ से अधिक है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 फीसदी है। यह केवल जनसंख्या का आँकड़ा नहीं, बल्कि भारत की जीवंत, प्राचीन और बहुविध सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय स्वरूप है। यह समुदाय न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संवाहक रहा है, बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं, भाषा-भाषाई विविधता और मौलिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक पहचान को निर्मित करता रहा है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इनके पराक्रम, बुद्धिमत्ता और प्रकृति से गहरे संबंध का उल्लेख मिलता है।

फिर भी, लंबे समय तक आदिवासी समाज को मुख्यधारा के विकास से दूर रखा गया। उन्हें एक जीवित संस्कृति के संरक्षक के रूप में तो देखा गया, पर समान भागीदार के रूप में नहीं। विशेषकर आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व, कौशल, सामाजिक समझ और समुदाय निर्माण में उनकी भूमिका को लंबे समय तक वह मान्यता नहीं मिली, जिसकी वे वास्तविक हकदार थीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सोच और व्यवस्था में स्पष्ट तथा उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार ने टोकनिज़्म (प्रतीकात्मक पहल) से आगे बढ़कर टार्गेटिड एम्पावरमेंट (लक्ष्य आधारित सशक्तिकरण) की नीति अपनाई है। जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के प्रति यह प्रतिबद्धता इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा में अब कोई भी समुदाय पीछे न रह जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र इसी समावेशी दृष्टि का सशक्त उदाहरण बन चुका है।

सावित्री ठाकुर

इसी प्रतिबद्धता का प्रभाव बजट आवंटन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जनजातीय समुदायों के विकास हेतु कुल बजट 2024-25 में ₹10,237.33 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹14,925.81 करोड़ हो गया है, जो 45.79 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यदि दीर्घकालीन दृष्टि से देखें, तो 2014-15 में ₹4,497.96 करोड़ के बजट के मुकाबले यह राशि पहले 2021-22 में ₹7,411 करोड़ तक पहुँची और अब यह वृद्धि 231.83 फीसदी तक पहुँच गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बढ़े हुए आवंटन से स्पष्ट है कि अब आदिवासी समुदाय, खासकर महिलाएँ, विकास की यात्रा में केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका में है।

जनजातीय समुदायों के विकास हेतु कुल बजट 2024-25 में रु. 10,237.33 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में रु.14,925.81 करोड़ हो गया है, जो 45.79 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यदि दीर्घकालीन दृष्टि से देखें, तो 2014-15 में रु.4,497.96 करोड़ के बजट के मुकाबले यह राशि पहले 2021-22 में रु.7,411 करोड़ तक पहुंची और अब यह वृद्धि 231.83 फीसदी तक पहुंच गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बढ़े हुए आवंटन से स्पष्ट है कि अब आदिवासी समुदाय, खासकर महिलाएँ, विकास की यात्रा में केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका में हैं।

भारत की आदिवासी महिलाएँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की धुरी रही हैं। वे जल, जंगल और जमीन से जुड़ी पारंपरिक जीवन व्यवस्थाओं की संरक्षक हैं और सामुदायिक निर्णय, संसाधन प्रबंधन और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज यह भूमिका केवल पारिवारिक और सामुदायिक स्तर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि शासन व्यवस्था से लेकर नीति निर्माण तक दिखाई दे रही है। इस परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली प्रतीक यह है कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं।

सरकार ने आदिवासी महिलाओं के सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक उत्थान एवं उनके नेतृत्व को संस्थागत आधार प्रदान करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे विकास केवल सुविधाओं का विस्तार न होकर, सम्मान, पहचान और आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करे। इनमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए ₹2 लाख तक का ऋण मात्र 4 फीसदी ब्याज दर पर प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे हस्तशिल्प, कृषि-आधारित कार्य, बांस उत्पाद, पशुपालन, प्रसंस्करण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता विकसित कर रही हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) इन समुदायों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचा रहा है। यह अभियान 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 75 PVTG समुदायों के उन इलाकों में विकास सुनिश्चित कर रहा है, जो लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहे हैं। लगभग ₹24,104 करोड़ के निवेश के साथ PM-JANMAN आवास, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा, सड़क संपर्क और सतत आजीविका जैसे क्षेत्रों में समग्र सुधार ला रहा है। इसके अतिरिक्त, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (एमडब्ल्यू) आदिवासी बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनके कौशल विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। साथ ही, छात्रवृत्ति योजनाओं ने विशेष रूप से बालिकाओं में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

DAY-NRLM ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं की वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता, सामूहिक उत्पादन, विपणन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया है। वहीं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान ने गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर और मातृ-स्वास्थ्य संकेतकों को सुधारने का कार्य किया है। पेसा (PESA) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के माध्यम से पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन की शक्ति दी गई है। इस कानून ने पंचायत और ग्राम सभा में महिला भागीदारी को संरचनात्मक स्तर पर सुनिश्चित किया है, जिसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए विशेष नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए है।

आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है। इस अभियान के तहत 20 लाख से अधिक परिवर्तनकारी प्रतिनिधियों (Change Agents), जिनमें महिला स्वयं-सहायता समूहों की सदस्याएँ, युवा और स्थानीय अधिकारी शामिल है, को शासन, सेवा वितरण और सामुदायिक सशक्तिकरण में स्थानीय नेतृत्व के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। अभियान का लक्ष्य ₹1 लाख जनजातीय गाँव विज़न 2030 के माध्यम से सहभागी शासन प्रणाली को मजबूत करना है, जिसमें महिलाओं की केंद्रीय भूमिका सुनिश्चित की गई है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस अभियान की सराहना की है और कहा है कि जमीनी स्तर पर आदिवासी नेतृत्व ही विकसित भारत@2047 की आधारशिला है। आज अनेक जनजातीय बहुल गाँवों में महिलाएँ ग्राम संस्थाओं की अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रही है।

साथ ही, वर्ष 2024 में शुरू धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों में समग्र विकास के लिए ₹79,000 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका एक मुख्य आधार ग्राम समितियों में महिलाओं की प्रत्यक्ष नेतृत्व भूमिका को मजबूत करना है।

वन आधारित आजीविका और हस्त-उद्यमों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में है, जिससे उनके कार्य का मूल्य और सम्मान दोनों बढ़े। स्वयं सहायता समूहों और आजीविका समूहों के माध्यम से महिलाएँ समाज में सकारात्मक परिवर्तन की सशक्त वाहक बन रही है। इस दिशा में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण को और व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही, आदिवासी बालिकाओं की उच्च शिक्षा और कौशल विकास तक पहुँच को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ भविष्य के नेतृत्व पदों तक आगे बढ़ सकें। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है- आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण केवल सामाजिक संवेदना का विषय नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक विस्तार, सतत विकास और समावेशी प्रगति की सबसे मज़बूत नींव है।

(लेखिका महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री, भारत सरकार हैं)